E-Paper : www.goodluckpublications.com, ● www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 317 | गुवाहाटी | मंगलवार, 23 जून, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखें कार्यकर्ता : नितिन नवीन पेज 2
पूर्वोत्तर का आर्थिक शक्ति केंद्र बनकर उभर रहा है असम : भाजपा पेज 3
मुख्यमंत्री योगी ने फिरोजाबाद को दी 658 करोड़ की 81 परियोजनाओं की ... पेज 5
फीफा विश्व कप 2026 : मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर दर्ज की... पेज 7

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, 18 बच्चों की मौत

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

दोषियों पर होगा एक्शन : सीएम

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित पुरनिया में एक तीन मंजिला बिल्डिंग में चल रही कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। इस घटना में 18 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना पर दुख जताते हुए बताया कि रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है। सोमवार दोपहर अलीगंज थाना क्षेत्र में स्थित पुरनिया चौराहे के पास एक तीन मंजिला बिल्डिंग की नीचे स्थित दुकान में आग लग गई। इसी दुकान के ऊपर कोचिंग सेंटर है। धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप लेते हुए कोचिंग सेंटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। भयावह स्थिति देख कोचिंग सेंटर पर मौजूद कई विद्यार्थी अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद पड़े, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। अलीगंज और मड़ियांव थाना की पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़िया मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।

पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिलाधिकारी विशाख समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उपमुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी अपनी आंखों के सामने कई बच्चों को निकाला गया है। घटना में कई बच्चों की मौत हुई है। कोचिंग के अंदर धुआं बहुत ज्यादा भर जाने के कारण रेस्क्यू टीम को दीवार तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आग इतनी भयवाह थी कि अपनी जान बचाने के लिए दम घुटने और झुलसने के डर से कुछ छात्र और लोग इमारत -शेष पृष्ठ दो पर

डिप्टी सीएम ने की 14 मौतों की पुष्टि उच्च स्तरीय जांच के आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दुखद घटना में, एक कोचिंग सेंटर वाली इमारत में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्णिया इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चल रहा था। जब घने धुएं और आग की लपटों ने इमारत के कुछ हिस्सों को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया, तो कई छात्रों को अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे अभी लखनऊ में हुई एक घटना के बारे में जानकारी मिली है। वहां -शेष पृष्ठ दो पर

कामाख्या में अंबुवासी मेले का शुभारंभ पर्यटन मंत्री अजंता नेओग ने किया उद्घाटन

गुवाहाटी (हि.स.)। नीलांचल पहाड़ स्थित देश की प्रमुख शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर परिसर में आयोजित अंबुवासी मेला का सोमवार को आध्यात्मिक वातावरण में शुभारंभ हुआ। पर्यटन मंत्री अजंता नेओग ने पांडु पोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि 22 जून की रात 09 बजकर 08 मिनट 42 सेकंड पर प्रवृत्ति के साथ कामाख्या मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा तथा 26 जून को निवृत्ति के बाद विशेष पूजा-अर्चना के उपरांत मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु-संतों, तीर्थयात्रियों और देश-विदेश से पहुंचे पर्यटकों का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दीं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अजंता नेओग ने कहा कि अंबुवासी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि असम की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से कामाख्या मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे इस मेला के माध्यम से असम के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से पर्यटन विभाग राज्य सरकार के सहयोग से अंबुवासी मेले के आयोजन आयोजन में अपना हाथ बंटा रहा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते हैं। वर्ष 2024 और 2025 में लगभग 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने मेले में भाग लिया था, जबकि इस वर्ष 08 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सुरक्षा तथा सूचना सहायता केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से मेले में भाग ले सकें। उन्होंने मेले में सहयोग प्रदान करने वाले विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए आम जनता से भी अतिथियों की -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

असम विस में 47 नए विधायकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन

गुवाहाटी। असम विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 4 और 5 जुलाई को गोपीनाथ बरदलै भवन में आयोजित किया जाएगा। कुल 47 विधायकों के इस प्रशिक्षण से गुजरने की उम्मीद है, जो विधानसभा के नियमों, प्रक्रियाओं और कामकाज पर केंद्रित होगा। हमारे पास 47 नए विधायक हैं जो विधानसभा की कार्यप्रणाली से अपरिचित हैं। इसलिए, हमने उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना महत्वपूर्ण समझा। यह प्रशिक्षण 4 और 5 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, असम विधानसभा अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ विधायकों का भी सत्रों में भाग लेने के लिए स्वागत है। यदि कोई भाग लेना चाहता है, तो वह गोपीनाथ बरदलै भवन आ सकता है। व्यवस्था के बिंदु, विशेष उल्लेख और अन्य विधायी प्रक्रियाओं सहित कई विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य के 40 हजार स्कूलों में सरकार ने ओलंपिक वैल्यूज प्रोग्राम शुरू किया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता पर बल्कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) के माध्यम से छात्रों में अनुशासन, टीम वर्क और जीवन कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, शर्मा ने शिक्षा प्रणाली में ओलंपिक मूल्यों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने लिखा कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से, हम इन पाठों को असम भर के 40,000 से अधिक स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं और एक ऐसी पीढ़ी का पोषण कर रहे हैं जो कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार है। शर्मा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम असम के सभी 35 जिलों में शुरू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच ओलंपिक आंदोलन के मूल मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना, शैक्षणिक एकाग्रता में सुधार करना, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना और आवश्यक जीवन कौशल विकसित करना है। साथ ही, इसका लक्ष्य शिक्षकों को मूल्य-आधारित शिक्षा को कक्षा शिक्षण में शामिल करने के लिए आवश्यक उपकरण और पद्धतियां प्रदान -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात
सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ। ये तुम्हे खत्म कर देगा।
- आचार्य चाणक्य

वैश्विक स्तर पर बढ़ा राज्य पर भरोसा : डॉ. शर्मा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि असम के सकारात्मक परिवर्तन की कहानी को अब विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाने लगा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी असम पर लागू यात्रा परामर्श (ट्रैवल एडवाइजरी) हटा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक कूटनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि असम में स्थापित शांति, विकास और स्थिर वातावरण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए ठोस और परिवर्तनकारी प्रयासों के कारण वैश्विक साझेदार अब असम को नए नजरिए से देख रहे हैं। डॉ. शर्मा ने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय उद्योगों, होमस्टे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और निवेश -शेष पृष्ठ दो पर

श्यामकानु महंत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के प्रसिद्ध संगीतकार जुबीन गर्ग की मृत्यु से जुड़े चर्चित मामले में मुख्य आरोपितों में शामिल श्यामकानु महंत ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौहाटी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महंत की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। इससे पहले विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने इसी मामले में आरोपित संदीपन गर्ग, अमृतप्रभा महंत, नंदेश्वर -शेष पृष्ठ दो पर

पश्चिम बंगाल में 4.38 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश

एक लाख सरकारी नौकरियां, डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त ने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य में रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश और आधारभूत संरचना के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्ति, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी वृद्धि, बेरोजगार युवाओं के लिए नई सहायता योजना तथा कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचित ऋण विरासत में मिला है। इसके बावजूद सरकार विकास -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में सुरक्षा बलों-प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, तीन घायल

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर सोमवार को आयोजित आपातकालीन बंदी प्रदर्शन हिंसक हो गया। न्यू कीथेलमनबी क्षेत्र में राजमार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में कम से कम तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुकी नागरिक समाज संगठनों द्वारा बुलाया गया राजमार्ग बंद लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी कुकी बहुल गांवों में कथित रूप से -शेष पृष्ठ दो पर

पूरे पूर्वोत्तर में से असम में सबसे ज्यादा एचआईवी के मामले दर्ज किए गए : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर में एचआईवी से पीड़ित लोगों (पीएलएचआईवी) की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य असम बनकर उभरा है, जो सरकार द्वारा निरंतर जागरूकता अभियानों और लक्षित हस्तक्षेपों के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती की गंभीरता को रेखांकित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, असम में वर्तमान में 33,145 लोग एचआईवी से पीड़ित हैं, जो राज्य में अनुमानित 0.13 प्रतिशत प्रसार दर को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार, असम पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्यों से संख्या में आगे है। मिजोरम में 26,321 एचआईवी संक्रमित हैं, जबकि नागालैंड में 23,731 और मणिपुर में 23,463 मामले हैं। त्रिपुरा में 10,769 मामले, मेघालय में 9,244, अरुणाचल प्रदेश में 2,630 और सिक्किम में 533 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े इस क्षेत्र की अनूठी जनसांख्यिकीय और महामारी संबंधी वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। असम का सूची में शीर्ष पर होना न केवल इसकी विशाल जनसंख्या के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए भी कि यह पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाला एक -शेष पृष्ठ दो पर

वंदे मातरम् और यूसीसी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीबीएलबी) के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि कल हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एआईएमपीबीएलबी ने देश को खासतौर से मुस्लिमों को जो दिक्कत हो रही है उस पर चिंता व्यक्त की है। इलियास ने आगे कहा कि मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, मस्जिद मदरसों में जो डिमोलिशन हो रहे हैं उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान आदि में उस पर चिंता व्यक्त की, भाजपा शासित राज्यों में वंदेमातरम को अनिवार्य किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। इलियास ने आगे कहा कि कुछ राज्यों के यूसीसी को पास किया गया इस पर भी चिंता व्यक्त की गई। ऐसा लग रहा है मुस्लिम -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

कवैमारी रिजर्व की 22 हजार बीघा भूमि पर जल्द चलेगा बेदखली अभियान

बजाली (हि.स.)। असम के बजाली जिले में स्थित कवैमारी रिजर्व की लगभग 22 हजार बीघा भूमि पर जल्द ही अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। यह घोषणा स्थानीय विधायक धर्मेश्वर राय ने की है। विधायक राय ने कहा कि कवैमारी रिजर्व की बड़ी मात्रा में भूमि संदिग्ध नागरिकों के कब्जे में है। आरोप है कि कई परिवारों ने रिजर्व क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वहां तालाबों की खुदाई के साथ-साथ तामूल (सुपारी) एवं पान की खेती भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर वहां गोरुखुटी परियोजना की तर्ज पर एक विकासात्मक परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और शीघ्र ही व्यापक उच्छेद अभियान चलाया जाएगा। विधायक ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कर उसका उपयोग जनहित और कृषि एवं पशुपालन आधारित विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखें कार्यकर्ता : नितिन नवीन

लुधियाना (हि.स.)। पंजाब के तीन दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को लुधियाना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव पंजाब की सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और राज्यभर में भाजपा का कैडर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना होगा। बैठक में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और आरके गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, अश्वनी शर्मा, सुनील जाखड़, नरिंदर रामूवालिया और इकबाल सिंह लालपुरा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लुधियाना बस स्टैंड के पास एक होटल में हुई इस बैठक में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। इनमें विजय सांपला, मनोरंजन कालिया, अविनाश राय खन्ना, मनप्रीत सिंह बादल, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, तीक्ष्ण सूद और अरुणेश शंकर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुसार नितिन नवीन का मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व का संदेश साफ था कि फिलहाल संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर ध्यान दिया जाए, जबकि गठबंधन से जुड़े फैसले केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ेर जाएं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी पंजाब में अपनी संगठनात्मक ताकत को स्वतंत्र रूप से परखना चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले खुद को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नितिन नवीन ने पंजाब के युवाओं से भी संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने कानून-व्यवस्था, रोजगार और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में 40 वर्ष से कम आयु के करीब 100 युवाओं ने हिस्सा लिया और पंजाब के विकास, शासन व्यवस्था और भविष्य के अवसरों को लेकर सुझाव दिए। दौरे के बाद दोपहर में अधिकांश वरिष्ठ नेता हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली रवाना हो गए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और नितिन नवीन की हलवारा में मुलाकात हुई, जिसके बाद वे कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ एक ही उड़ान से दिल्ली लौटे।

बंगाल की राजनीति में नया मोड़

ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से बाहर अभिषेक निलंबित, ऋतब्रत ने बनाई नई कमेटी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर चल रहा सत्ता संघर्ष और गहरा गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, बागी विधायक नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को *असली टीएमसी* बताते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी को पद से हटाने और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी को निलंबित करने का एलान किया है। रविवार को न्यू टाउन स्थित एक होटल में ऋतब्रत गुट की बैठक हुई। इस गुट का दावा है कि इस बैठक में 60 विधायक और कोलकाता नगर निगम के 70 पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में हावड़ा मध्य से विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऋतब्रत बनर्जी गुट का कहना है कि पार्टी में *संवैधानिक संकट* पैदा हो गया था। उनका दावा है कि टीएमसी के संविधान के अनुसार हर तीन साल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए। आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनी थी और उसके बाद संगठन का पुनर्गठन नहीं किया गया। ऋतब्रत बनर्जी ने बैठक में कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी संगठनात्मक ढांचे का नवीनीकरण नहीं किया गया, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने ऋतब्रत बनर्जी को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। अब बागी गुट ने पलटवार करते हुए नया संगठन घोषित कर दिया है। ताजा घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस तीन हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। पहला गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला मूल टीएमसी है। दूसरा ऋतब्रत बनर्जी का असली टीएमसी गुट है, जो अब विधानसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर रहा है। वहीं तीसरा गुट करीब दो दर्जन लोकसभा सांसदों का बताया जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है।

शिवसेना यूबीटी के छह बागी सांसद शिंदे समूह में शामिल

मुंबई (हि.स.)। शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद सोमवार को मुंबई में स्थित यशवंतराव सभागृह में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना शिंदे समूह में शामिल हो गए। इन सभी का उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी में स्वागत किया और कहा कि सभी सांसदों का उचित सम्मान किया जाएगा। साथ ही इन सभी सांसदों के कार्यक्षेत्र में विकास कार्य को प्रमुखता दी जाएगी। मुंबई के यशवंत राव सभागृह में आज धाराशिव से ओमराजे निंबालकर, परभणी से संजय जाधव, मुंबई उत्तर-पूर्व से संजय दीना पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टिकर, शिरडी से भाऊसाहेब वाकचौरे और यवतमाल-वाशिम से संजय देशमुख ने शिवसेना शिंदे समूह में विधिवत शामिल हो गए। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कानूनी दायरे में किया गया है। इससे पहले 2022 में उन्होंने शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए 40 विधायकों को लेकर क्रांति की थी, जो अब बढ़कर करीब 60 विधायकों तक पहुंच चुकी है। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि यह सभी छह सांसद उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आम जनता में जाएंगे और चुन कर आएंगे। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इन सांसदों को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चा की जा रही थी। उन्होंने शिवसेना यूबीटी पर तंज कसते हुए कहा कि जब वे बालासाहेब के विचारों से हट गए, तब उन्हें बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए क्रांति करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ गाली देते हैं, हमारा फोकस सिर्फ लोगों के काम पर है।

जयपुर में जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज

जयपुर (हि.स.)। राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने राजधानी जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला पिछले कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थी। वह सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों और कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एटीएस ने बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा (37) को जयपुर के वाटिका क्षेत्र से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर क्षेत्र की रहने वाली महिला वर्तमान में जयपुर में अपने सेवानिवृत्त पिता के साथ रह रही थी। एटीएस के अनुसार महिला के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान सहित विदेशी नंबरों से बातचीत के संकेत मिले हैं। उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे कई प्रोफाइल पाए गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और अन्य उग्रवादी संगठनों से संबंधित सामग्री, झंडे और हथियारबंद आतंकियों की तस्वीरें मौजूद थीं। एटीएस के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि एजेंसियों को आशंका है कि महिला को कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए प्रभावित कर आतंकी संगठन के लिए तैयार किया जा रहा था। जांच में महिला के मोबाइल फोन से दो सिम कार्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और कई विदेशी संपर्कों के प्रमाण मिले हैं। एटीएस को शक है कि महिला को नेपाल, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। महिला के मोबाइल से पाकिस्तान को कुछ दस्तावेज और अन्य जानकारियां भेजे जाने के संकेत भी मिले हैं। हालांकि उसने मोबाइल का काफी डेटा डिलीट कर दिया था, जिसे अब फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से रिकवर किया जा रहा है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि पिछले छह-सात महीनों से महिला का धर्म परिवर्तन कराने और उसके माध्यम से भारत में गतिविधियां संचालित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि सभी तथ्यों की डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि महिला केवल ऑनलाइन संपर्कों तक सीमित थी या किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा भी थी।

ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से पहले ईरान और इथियोपिया के नेताओं से मिले अजीत डोभाल

नई दिल्ली (हि.स.)। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेने भारत आए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव घादिर नेजामी और अफ्रीकी देश इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण विभाग के कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तदेस्से से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी दी कि एनएसए अजीत डोभाल ने 22 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक के दौरान ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव घादिर नेजामीपुर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। साथ ही ब्रिक्स मंच के तहत सहयोग और भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार-विमर्श किया। भारत में ईरानी दूतावार से एक्स पोस्ट में बताया कि अपनी यात्रा के दौरान घादिर नेजामी विभिन्न विशेष सत्रों में भाग लेंगे और सहभागी देशों के अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा मुद्दों तथा बहुपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श करेंगे। बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। एक अन्य पोस्ट में रणधीर जायसवाल ने बताया कि एनएसए अजीत डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण विभाग के कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तदेस्से से भी मुलाकात की।

पृष्ठ एक का शेष

लखनऊ के कोचिंग...

की ऊपरी मंजिलों से सीधे नीचे कूद गए। इससे उन्हें चोटे आई हैं। जब यह घटना हुई उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली। उन्होंने सभा के मंच से ही इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी-अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुखद घटना हुई है, उसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं, उनकी दुखद मौत हुई है, इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है। जिन्होंने जान खोई उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस पूरे मामले के लिए पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां प्रस्थान कर रहा हूं जिससे इस पूरे मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपए तथा घायलों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।

डिप्टी सीएम ने की 14 ...

आग लगने की घटना में कुछ बच्चे फंस गए थे, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन इस दुखद घटना के कारण मुझे तुरंत लखनऊ लौटना पड़ रहा है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा करें और इस मामले पर रिपोर्ट सौंपें। हम इस घटना की तह तक जाएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अलीगढ़ का दौरा अलग से करूंगा। घटना स्थल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अभी कुल तेरह बच्चों को बाहर निकाला गया है। उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। यह एक बड़ी घटना है। अंदर धुआं भरा है। हर चीज को हटाकर और चेक किया जा रहा है, और हर कमरे की तलाशी ली जा रही है; अंदर लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर था, और उस फर्नीचर से निकलने वाले धुएं के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग अचानक लगी; यह एक एनिमेशन सेंटर था। उन्होंने कहा कि बच्चे यहां एनिमेशन—यानी कार्टून बनाना—सीखने आते थे। मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना असल में कैसे शुरू हुई... घायलों को केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल थी... घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी को मौके पर बुलाया गया है और उन्हें कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं।

कामाख्या में अंबुवासी ...

सेवा कर इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक विजय गुप्ता, असम पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ऋतुपर्ण बरुवा, उपाध्यक्ष दिलीप दास, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कामाख्या मंदिर प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि, साधु-संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

असम विस में 47 नए...

जाएगा। विधायी कार्यप्रणाली के कई पहलू होने के कारण, कार्यक्रम को दो सत्रों में संरचित किया गया है, दास ने कहा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई प्रतिष्ठित हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. समुद्र गुप्ता कश्यप, पूर्व उपसभापति डॉ. नुमल मोमिन और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आमंत्रित विशेषज्ञों और पूर्व विधायकों द्वारा विधायी कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर सत्र आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

राज्य के 40 हजार स्कूलों ...

करके उन्हें सशक्त बनाना भी है। यह कार्यक्रम असम सरकार के समग्र शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो शैक्षणिक उपलब्धि के साथ-साथ चरित्र निर्माण पर भी जोर देता है। अधिकारियों का मानना है कि उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान, दृढ़ता और टीम वर्क जैसे ओलंपिक आदर्शों के संपर्क में आने से छात्रों को नेतृत्व के गुण और जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। शिक्षा विशेषज्ञों ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि मूल्यों पर आधारित शिक्षा ऐसे सर्वांगीण व्यक्तित्वों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो सामाजिक और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। ओलंपिक मूल्यों की शिक्षा कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेल और शिक्षा के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने के एक उपकरण के रूप में विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। असम में इस पहल के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से राज्य के उन प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है जो छात्रों के बीच शारीरिक गतिविधि, सामाजिक सामंजस्य और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हुए एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम अकादमिक शिक्षा को मूल्यों पर आधारित शिक्षा और जीवन कौशल विकास के साथ जोड़कर भावी पीढ़ियों को सफलता के लिए तैयार करने के प्रति असम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्यामकानु महंत ने सुप्रीम ...

बोरा और परेश बैश्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर उन्हें मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया था। श्यामकनु महंत ने इससे पूर्व गौहाटी हाईकोर्ट में भी जमानत की मांग की थी। न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जमानत देने की दलील पेश की, जबकि महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने इसका विरोध करते हुए याचिका खारिज करने का आग्रह किया था। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार जुबीन गर्ग की मृत्यु से जुड़े इस मामले ने पूरे असम में व्यापक जनचर्चा और कानूनी बहस को जन्म दिया है। मामले की आगे की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल में 4.38 लाख...

और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसके लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों को भरने का एलान किया है। प्रस्तावित नियुक्तियों में 20 हजार पद पुलिस विभाग में, 50 हजार पद राज्य संचालित विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षण कर्मियों के लिए तथा शेष 30 हजार पद अन्य सरकारी विभागों में भरे जाएंगे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर देने के उद्देश्य से कुल नियुक्तियों में 33 प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकतानुसार अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इसके बाद डीए 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधित दर एक अक्तूबर 2026 से प्रभावी होगी। वहीं नागरिक स्वयंसेवकों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की राशि 70 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे। बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 125 दिन की ग्रामीण कार्य योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की गई है। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए *नई भरोसा योजना* शुरू की जाएगी, जिसके तहत पात्र बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए प्रतिमाह तथा अन्य पात्र बेरोजगारों को 2,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 3,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से राज्य के लगभग सात करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के पीड़ित परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। झाड़ग्राम में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई है। नदिया जिले के कल्याणी में 1,500 एकड़ भूमि पर एक नए हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ रहे यात्री दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही उपयुक्त भूमि का चयन करेगी। इसके अलावा पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, जबकि कूचबिहार हवाई अड्डे के विस्तार की योजना भी बजट में शामिल की गई है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व मेदिनीपुर जिले के दादनपात्रबार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर एक गहरे समुद्री बंदरगाह की स्थापना की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य में समुद्री व्यापार को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा। साथ ही अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा स्थित भारतीय वायुसेना अड्डों के विस्तार में भी राज्य सरकार सहयोग करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शहरी भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 की समीक्षा की जाएगी।

मणिपुर में सुरक्षा बलों...

चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्र हुए और वाहनों की आवाजाही रोकते हुए सुरक्षा अभियानों को तत्काल बंद करने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों द्वारा उनके क्षेत्रों में चुनिंदा और लक्षित कार्रवाई की जा रही है, जिससे समुदाय के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थिति उस समय बिगड़ गई जब सुरक्षा बलों ने राजमार्ग पर यातायात बहाल कराने और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर ब्लैंक फायरिंग, स्मोक बम और अन्य दंगा-नियंत्रण उपायों का इस्तेमाल किया। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई लोग इधर-उधर भागने लगे। कुकी इनपी साउथ वेस्ट सदर हिल्स (केआईएसडब्ल्यू-एसएच) ने घटना की कड़ी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ब्लैंक गोला-बारूद का उपयोग किया और लाठीचार्ज किया। संगठन का दावा है कि झड़प में कम से कम तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अपने बयान में केआईएसडब्ल्यू-एसएच ने कहा कि प्रशासन ने लोगों की चिंताओं और शिकायतों को सुनने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाया है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन कुकी बहुल क्षेत्रों में कथित भेदभावपूर्ण और लक्षित तलाशी अभियानों के विरोध में शुरू किया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऐसे अभियानों को तुरंत रोका जाए और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया जाए। संगठन ने क्षेत्र में जारी जातीय तनावों के लिए एनएससीएन-आईएम और उसके कथित सहयोगी जेडयूएफ-कैमसन गुट को जिम्मेदार ठहराते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा तथा विरोध-प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

पूरे पूर्वोत्तर में से असम...

प्रमुख परिवहन और वाणिज्यिक केंद्र है। उच्च गतिशीलता, प्रवासन, शहरीकरण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के विभिन्न स्तर एचआईवी की रोकथाम और उपचार के प्रयासों को जटिल बना सकते हैं। असम में एचआईवी संक्रमण में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी अधिक है। पूर्वोत्तर में एचआईवी पॉजिटिव पाई गई 13,809 महिलाओं में से अकेले असम में 6,809 मामले हैं - जो कुल संख्या का लगभग आधा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि असम में 146 गर्भवती महिलाओं में एचआईवी संक्रमण पाया गया है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बाद नागालैंड में 127 और मेघालय में 124 मामले हैं। ये आंकड़े माता-पिता से बच्चे में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के कार्यक्रमों को मजबूत करने और समय पर प्रसवपूर्व जांच और उपचार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नेको) ने रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहायता को संयोजित करने वाली एक एकीकृत संचार रणनीति के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। जागरूकता बढ़ाने, परीक्षण को प्रोत्साहित करने और कलंक को कम करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहलों को एचआईवी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष कमजोरियों को पहचानते हुए, नेको ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट मल्टीमीडिया अभियान लागू किए हैं। युवाओं तक पहुंचने की इसकी प्रमुख पहलों में से एक, *रेड फेस्ट,* संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों का उपयोग करके एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाता है और युवाओं के बीच फैली भ्रांतियों और गलत धारणाओं का खंडन करता है। एचआईवी संक्रमण, रोकथाम और जोखिम कारकों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने पर भी गहन सूचना संचार और संचार अभियान चलाया गया है। साथ ही, भेदभाव से लड़ने और एचआईवी से पीड़ित लोगों की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक नेताओं, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए वकालत और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार और एचआईवी नियंत्रण उपायों में स्थानीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए एड्स पर राज्य परिषद की बैठकें आयोजित की हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि निरंतर सफलता प्रारंभिक निदान का विस्तार करने, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने, कलंक को कम करने और लक्षित हस्तक्षेपों के साथ कमजोर आबादी तक पहुंचने पर निर्भर करती है। प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुनीला गर्ग ने कहा कि असम के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि निरंतर प्रयासों के बावजूद, राज्य में इस क्षेत्र में एचआईवी का सबसे बड़ा बोझ बना हुआ है, इसलिए इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए रोकथाम, निगरानी और उपचार सेवाओं में निरंतर निवेश करना महत्वपूर्ण है।

वंदे मातरम् और यूसीसी ...

कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। नफरती भाषणों में भाजपा के लोग और सत्ता में बैठे लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय को टारगेट करके वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने फैसला लिया है हम डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे डिमोलिशन, लिंचिंग आदि पर और हम उसे जल्द रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। देश में शांति चाहने वालों को साथ लेकर कार्यक्रम होंगे। यात्राएं होंगी, कन्वेंशन होगी। वर्किंग कमेटी ने इस पर भी चिंता व्यक्त की है कि सेकुलर दलों को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा रहे हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जहां जहां भी यूसीसी लागू किया जाएगा, वहां हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उन्होंने कहा कि वंदेमातरम हमारा ऐतराज सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आनंद मठ का हिस्सा बल्कि देवी देवताओं के वंदन की बात है और इस्लाम में एकेश्वरवाद सिद्धांत से टकराता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ा हो जाना गलत नहीं है, लेकिन उसके गायन को अनिवार्य करना ये संविधान से टकराता है और ये गलत है। कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है कि मुस्लमानों को पढ़ना अनिवार्य नहीं है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ा राज्य ...

के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि असम अब वैश्विक अवसरों और साझेदारियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने नागरिकों को असम की यात्रा से बचने की सलाह देता था, लेकिन आज राज्य में हुए व्यापक बदलावों के कारण कई देश और वैश्विक साझेदार ऐसी सलाहों को वापस लेते हुए असम की संभावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर का आर्थिक शक्ति केंद्र बनकर उभर रहा है असम : भाजपा

गुवाहाटी (हि.स.)। भाजपा असम प्रदेश की प्रवक्ता डॉ. जाफरीन मेहजाबिन ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति कर रहा है और पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील नीतियों, संस्थागत सुधारों, आधारभूत संरचना के विस्तार और वैश्विक निवेशकों के साथ बढ़ते संपर्क के कारण असम ने विकास की नई दिशा प्राप्त की है। एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं आधारभूत संरचना शिखर सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री द्वारा जापान, सिंगापुर सहित विभिन्न देशों में किए गए निवेश संपर्क कार्यक्रमों ने राज्य के प्रति वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। डॉ. मेहजाबिन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय संघ के कई देशों द्वारा असम के अधिकांश हिस्सों के लिए यात्रा सलाह में ढील देना राज्य की बेहतर कानून-व्यवस्था, सुशासन और आर्थिक संभावनाओं की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। इससे पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा, आधारभूत संरचना, हाइड्रोकार्बन, विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग दो लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन के तहत हैं, जबकि 1.21 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 70 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है। डॉ. मेहजाबिन ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने जगीरोड में स्थापित हो रही टाटा सेमीकंडक्टर ओएसएटी परियोजना को असम और पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि निवेशकों का बढ़ता विश्वास, तेज औद्योगिकीकरण और प्रभावी नीति क्रियान्वयन असम को राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कृषक पंजीकरण प्रक्रिया तेज करने का निर्देश

कृषि मंत्री पीयूष ने जिला आयुक्तों के साथ की बैठक

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने सोमवार को जनता भवन स्थित अपने कार्यालय से राज्य के विभिन्न जिलों के जिला आयुक्तों एवं जिला कृषि अधिकारियों के साथ एक विस्तृत वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के पट्टाधारकों के डिजिटलीकरण, फार्मर रजिस्ट्री (एफआर) आईडी सृजन, एग्री स्टैक के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत धान खरीद व्यवस्था, लघु चाय उत्पादकों एवं निजी भूमि पर खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण, गांव आधारित हायरार्की मैपिंग, जिला स्तर पर किसान पहचान पत्र निर्माण तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने राज्यभर में किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि असम के लगभग 50 लाख किसान परिवारों को पंजीकरण के दायरे में लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य की दो करोड़ से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला आयुक्तों और जिला कृषि अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में पंजीकरण अभियान को और अधिक गति देने के निर्देश दिए। हजारिका ने कहा कि किसानों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्मरण कराया कि समय पर पंजीकरण होने से ही किसान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में मंत्री ने एनएमईओ-ओपी कार्यक्रम के तहत ऑयल पाम की खेती के विस्तार में सक्रिय सहयोग देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऑयल पाम की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मंत्री ने कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, आंकड़ों के सटीक समेकन तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। उन्होंने किसान-केंद्रित, प्रौद्योगिकी आधारित और अधिक पारदर्शी कृषि व्यवस्था विकसित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में कृषि विभाग की आयुक्त एवं सचिव अरुणा राजोरिया, भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक कैलाश कार्तिक तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इंडियन ऑयल रिफाइनरी ने बंगाईगांव जिले को 102.62 लाख की सीएसआर परियोजनाएं सौंपीं

बंगाईगांव (हि.स.)। समावेशी सामुदायिक विकास और समाज कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, इंडियन ऑयल बंगाईगांव रिफाइनरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बंगाईगांव जिले के विभिन्न लाभार्थी संगठनों और सरकारी विभागों को ?102.62 लाख की छह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाएं औपचारिक रूप से सौंपीं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के लिए दो बोलेरो वाहन, एमजी मॉडल अस्पताल, सृजनग्राम के लिए एक एम्बुलेंस, जिला टीबी केंद्र के लिए हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन, जिला अस्पतालों के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन (सीबीई) उपकरण, फीडिंग रूम के साथ दो महिला शौचालय ब्लॉक, और जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए डबल-सिलेंडर रिफिल सुविधा के साथ 82 एलपीजी कनेक्शन शामिल हैं। इस समारोह में बरपेटा के सांसद फणिभूषण चौधरी, बंगाईगांव की विधायक दीप्तिमयी चौधरी, बंगाईगांव जिला विकास आयुक्त आरके दास, एनके बरुवा, कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख, बंगाईगांव रिफाइनरी और इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद चौधरी ने सामुदायिक कल्याण के प्रति इंडियन ऑयल के निरंतर प्रयासों की सराहना की और कहा कि इंडियन ऑयल ने इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार प्रदर्शित किया है। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगी और बंगाईगांव जिले के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। इस तरह की पहल जनता तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने में सरकार के प्रयासों को पूरक बनाती हैं। विधायक ने रिफाइनरी की जन-केंद्रित सीएसआर पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सौंपी गई परियोजनाएं सीधे तौर पर महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, महिला कल्याण और बाल विकास के क्षेत्र में। स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान जिले भर में महिलाओं और बच्चों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जिला विकास आयुक्त ने जिला विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से इंडियन ऑयल द्वारा दिया गया सहयोग विभिन्न सरकारी विभागों की सेवा वितरण क्षमताओं को बढ़ाएगा। जिला प्रशासन जिले की महत्वपूर्ण विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें पूरा करने में इंडियनऑयल की सक्रिय भूमिका की सराहना करता है। सभा को संबोधित करते हुए एनके बरुवा ने कहा कि इंडियन ऑयल में हमारा मानना है कि सतत विकास केवल व्यावसायिक संचालन तक सीमित नहीं है। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, हम समाज के लिए सार्थक और स्थायी मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, महिला कल्याण को बढ़ावा देने और हमारे संचालन क्षेत्रों और उसके आसपास सामुदायिक विकास को समर्थन देने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती हैं। लाभार्थियों ने निरंतर सहयोग के लिए इंडियन ऑयल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और समुदाय के लाभ के लिए इन संपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग का आश्वासन दिया।

गुवाहाटी से दुबई और अबूधाबी के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान सेवा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि आगामी 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबूधाबी के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह नई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी असम के व्यापार, निवेश, पर्यटन और वैश्विक संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों द्वारा असम के लिए जारी यात्रा परामर्श हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया द्वारा संचालित इन नॉन-स्टॉप उड़ानों के शुरू होने से गुवाहाटी हवाई अड्डा अब संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान सहित चार देशों से सीधे जुड़ जाएगा। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह कदम गुवाहाटी को दक्षिण-पूर्व एशिया का एक प्रमुख यात्रा और ट्रांजिट केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा प्रोत्साहन देगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनकी अगली प्राथमिकता गुवाहाटी से वियतनाम के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करना है।

बेदखली अभियान और महंगाई को लेकर केंद्र व असम सरकार पर अजमल का निशाना

गुवाहाटी (हि.स.)। एआईयूडीएफ प्रमुख और विधायक बदरुद्दीन अजमल ने सोमवार को केंद्र और असम की भाजपा सरकार पर बेदखली अभियानों, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त पुनर्वास सहायता नहीं मिल रही है। असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने अजमल को विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में अजमल ने कहा कि वह अपनी पार्टी के निर्देश पर राज्य स्तरीय राजनीति में आए और जनता के समर्थन से निर्वाचित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों की आलोचना करते हुए दावा किया कि देशभर में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है। असम में जारी बेदखली अभियानों पर चिंता जताते हुए अजमल ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों की पहचान के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियानों के दौरान कई वास्तविक भारतीय नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी बेदखली अभियान से पहले प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। एआईयूडीएफ नेता ने महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को भी जनता की प्रमुख चिंता बताया। रसोई गैस सिलेंडर और ईंधन की बढ़ती कीमतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि

धेमाजी में भीषण सड़क हादसा, दो बैंक कर्मचारियों की मौत

धेमाजी (हि.स.)। असम के धेमाजी जिले के हाहचरा क्षेत्र में रविवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) धेमाजी शाखा के दो कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान एसबीआई धेमाजी शाखा के कैशियर हिरकज्योति मिली तथा अकाउंट्स स्टाफ रातुल कोंवर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों एक वाहन से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण वाहन सड़क से फिसलकर पानी में जा गिरा।

दोतमा विकास खंड में जन कल्याण शिविर का आयोजन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उमड़ी भीड़

कोकराझाड़, 22 जून। सरकार के 12 वर्षों के *सेवा, संकल्प, विकास और जन भागीदारी* के सफर को चिह्नित करने के उपलक्ष्य में, दोतमा विकास खंड में दो दिवसीय *जन कल्याण शिविर* का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 22 और 23 जून, 2026 तक आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम जनता के द्वार तक पहुंचाना और विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। योजनाओं का लाभ और पंजीकरण: केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है और नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु विशेष काउंटर बनाए गए हैं। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित डेस्क कार्यरत है। शिविर में उपस्थित अधिकारियों के साथ नागरिकों को सीधे बातचीत करने और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। यह शिविर समाज के सभी वर्गों के लिए है, जिसमें किसान, कृषि श्रमिक, चाय बागान श्रमिक, महिला स्वयं सहायता समूह, छात्र-छात्राएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और पथ विक्रेता शामिल हैं। जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है।

रंगिया : सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्रक मुख्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित

रंगिया। रंगिया के मोरानजना स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएबी) के क्षेत्रक मुख्यालय द्वारा अपने 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल में क्षेत्रक मुख्यालय के अधिकारियों और जवानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज सेवा और मानव कल्याण के प्रति अपनी संवेदनशीलता तथा प्रतिबद्धता का परिचय दिया। शिविर का संचालन 24वीं वाहिनी की उप कमांडेंट (चिकित्सा) डॉ. बंदना देवी खारीबम और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) ब्लड बैंक की डॉ. अरुणिमा गोस्वामी की देखरेख में हुआ। इस दौरान चिकित्सा से जुड़े सभी आवश्यक नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया। सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित इस शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

अजगर सांप पकड़कर लोगों ने वन विभाग को सौंपा

तिनसुकिया (हि.स.)। तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा समजिला के लेखापानी थाना अंतर्गत एक नंबर लोंगटोंग स्थित निजी चाय बागान में एक विशालकाय अजगर दिखाई देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अजगर को देखकर बागान कर्मियों और स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। इस बीच एक स्थानीय युवक की सूझबूझ और साहसिक पहल के कारण अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने तत्काल लेखापानी वन कार्यालय को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आए और वन कर्मियों की एक टीम आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से अजगर को अपने कब्जे में लेकर उसका प्राथमिक निरीक्षण किया।

पुलिस के जाल में मोस्ट वांटेड उस्मान अली

विश्वनाथ (हि.स.)। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विश्वनाथ पुलिस ने मोस्ट वांटेड तस्कर उस्मान अली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उसे गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश जा रही एक रात्रिकालीन बस में अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान उस्मान अली के बैग से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह इस मादक पदार्थ की खेप को अरुणाचल प्रदेश में तस्करी के उद्देश्य से ले जा रहा था।

चिले नदी का कहर जारी, सोनारी में पांचवें दिन भी बाढ़ की स्थिति जस की तस

गुवाहाटी (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर आई चिले नदी का कहर जोनाई क्षेत्र में लगातार जारी है। बढ़ते जलस्तर के चलते सड़कें, घर-द्वार और विस्तृत कृषि भूमि जलमग्न हो गई हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राभाकाठनी, शांतिपुर और मालभोग गांवों के अधिकांश क्षेत्र बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण आवागमन बाधित हो गया है तथा कई विद्यालयों में पठन-पाठन भी बंद करना पड़ा है। स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, सोनारी में पांचवें दिन भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सोनारी नगर सहित आसपास के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर उनकी सुध न लेने का आरोप लगाया है। वार्ड संख्या-6 में कई परिवारों को एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अस्वास्थ्यकर वातावरण में रह रहे बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन से शीघ्र शुद्ध पेयजल और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर राहत नहीं पहुंची तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

नगांव के योग दिवस समारोह में शामिल हुए मंत्री केशव महंत

नगांव 22 जून। योगाभ्यास मनुष्य के मन और प्रकृति के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसलिए योग को जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह बात राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री केशव महंत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। नगांव जिला प्रशासन के तत्वावधान में तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन के सहयोग से नगांव शहर स्थित पुलिस रिजर्व के मुक्त प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्राचीन भारतीय सभ्यता की इस अमूल्य धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने सभी लोगों से नियमित रूप से योगाभ्यास जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नगांव-बटद्रवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूपक शर्मा ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य के प्रत्येक जिले, उप-जिले, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर तक योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों में योग के प्रति जागरूकता और रुचि काफी बढ़ी है। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण किंकर खटनियार ने किया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त देवयानी चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त कमलजीत शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. पंचम कुमार बोरा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विकास शर्मा, उपाध्यक्ष (नगरपालिका) सीमांत बोरा तथा आयुष के जिला नोडल अधिकारी डॉ. रीमा

पूसीरे के जीएम ने कामाख्या स्टेशन का निरीक्षण कर अंबुबासी मेले की तैयारियों का लिया जायजा

गुवाहाटी (हि.स.)। नीलाचल पहाड़ी पर स्थित विश्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या धाम में 22 से 25 जून तक आयोजित होने वाले अंबुबासी मेले के मद्देनजर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पूसीरे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को कामाख्या रेलवे स्टेशन का सघन निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अंबुबासी मेला पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तीर्थयात्रियों की इसी भारी आमद को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर और रेल परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यात्री सहायता केंद्र, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, हेल्प डेस्क, प्रतीक्षालयों की स्थिति तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन परिसर में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद कर मेला अवधि के दौरान संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी ली। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मियों को चौबीसों घंटे सतर्क रहकर कार्य करना होगा तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। उन्होंने यात्रियों की आवाजाही पर निरंतर निगरानी रखने, भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों, राज्य प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।

संपादकीय

राम नाम की लूट है...

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा-चोरी के संदर्भ में अब यह अहम सवाल है कि ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट के सदस्यों और उनके पालतू चंपुओं पर सिर्फ चढ़ावे की चोरी-डकैती के ही आरोप नहीं हैं, बल्कि भगवान राम को पहनाए गए, हीरे-जवाहरात के हार, चांदी की चरण-पादुका, अन्य गहने-आभूषण गायब करने के भी संवेदनशील आरोप हैं। फिर आरोपित राम मंदिर के ट्रस्ट में क्यों हैं? ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर राम मंदिर में ही इंजीनियर रहे दीनानाथ वर्मा के भ्रष्ट आरोप हैं कि वह निर्माण-कार्यों में 40 फीसदी कमीशन मांगते थे। फर्जी बिल बना कर निर्माण-कार्यों में मोटा घोटाला किया गया है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कीचड़ तो उछला है! सबसे अधिक आपत्तिजनक और अवैध यह माना जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल ने 'नजूल की जमीन' कैसे और क्यों खरीदी? एक उदाहरण सामने आया है कि 2.92 करोड़ रुपए की नजूल-भूमि 23-24 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी गई? नजूल की जमीन सरकारी संपत्ति होती है, जो राज्य सरकार को सौंपी जाती है। यह जमीन लीज, पट्टे पर तो दी जा सकती है, लेकिन इसे बेचा-खरीदा नहीं जा सकता। जमीन से जुड़ी ऐसी भ्रष्ट विसंगतियों के आरोप तब से लगाए जा रहे हैं, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था। अभी दो-तीन दिन पहले उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के प्रवास पर थे, लेकिन ट्रस्ट को स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि चंपत राय और अन्य आरोपितों, संदिग्धों को उनसे दूर रखा जाए। आखिर क्यों...? क्या विशेष जांच टीम ने मुख्यमंत्री को कुछ 'विस्फोटक खुलासे' किए हैं? चंपत राय समेत अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सुभाष श्रीवास्तव आदि पर संगीन आरोप हैं और सभी आरएसएस के पदाधिकारी रह चुके हैं। क्या सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए खामोश हैं? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके एवं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने टीवी चैनलों के साक्षात्कारों में चढ़ावा-चोरी को 'डाका' करार दिया है और नजूल की जमीन खरीदने पर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद चंपत राय की चारित्रिक निष्ठाएं गाई जा रही हैं कि वह पूजा की थाली का चावल तक चुरा नहीं सकते। फक्कड़ स्वभाव के और संत किस्म के व्यक्ति हैं। सवाल है कि जिस मंदिर में करोड़ों रुपए का दान आता हो, करोड़ों रुपए निर्माण और व्यवस्था पर खर्च किए जाते रहे हों, क्या उसके प्रशासन का दायित्व किसी 'संत-फकीर' को सौंपा जा सकता है? क्या ट्रस्ट भी 'दैवीय' है अथवा ट्रस्ट के सदस्य या संबद्ध लोग खास 'राम-भक्त' हैं? सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर, प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह ट्रस्ट गठित किया था। ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं, जो इसे खंडित नहीं किया जा सकता? वैसे अब चर्चा सुनी जा रही है कि एक हालिया सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाया जा सकता है, लिहाजा कुछ चेहरों पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल हमारी अगाध आस्था है कि प्रभु राम देश की आत्मा हैं, प्राण हैं, जिंदगी हैं, मन-विचार हैं, प्रार्थना हैं और असीमित मर्यादा हैं। करोड़ों राम-भक्तों की ऐसी आस्थाओं, भक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता। यह धारणा पैदा नहीं की जा सकती कि राम मंदिर भी लूट, चोरी-चकारी का अड्डा है। राम के प्रति जरा-सा भी मोहभंग यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई 'राम-नाम' की लूट नहीं मची है कि कोई भी लूट ले! सवाल यह भी बेहद गंभीर है कि राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और अखाड़ों के महामंडलेश्वर संतों को क्यों नहीं रखा गया? संघ परिवार का ही ट्रस्ट क्यों बना दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी तो 'परिवारवाद' के कट्टर विरोधी हैं। बहरहाल आरोप तो आंदोलन के दौरान असंख्य 'राम-शिलाओं' को लेकर भी सामने आए हैं। उनमें चांदी की शिलाएं भी थीं। यह चोरी-डकैती तिरुपति मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर आदि में भी होती रही है। करोड़ों की हेरा-फेरी, डकैती सामने आती रही है, लेकिन वक्त बीतने के साथ-साथ सब कुछ दब-ढक जाता है।

ट्रस्ट के सदस्यों और उनके पालतू चंपुओं पर सिर्फ चढ़ावे की चोरी-डकैती के ही आरोप नहीं हैं, बल्कि भगवान राम को पहनाए गए, हीरे-जवाहरात के हार, चांदी की चरण-पादुका, अन्य गहने-आभूषण गायब करने के भी संवेदनशील आरोप हैं। फिर आरोपित राम मंदिर के ट्रस्ट में क्यों हैं? ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर राम मंदिर में ही इंजीनियर रहे दीनानाथ वर्मा के भ्रष्ट आरोप हैं कि वह निर्माण-कार्यों में 40 फीसदी कमीशन मांगते थे। फर्जी बिल बना कर निर्माण-कार्यों में मोटा घोटाला किया गया है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कीचड़ तो उछला है! सबसे अधिक आपत्तिजनक और अवैध यह माना जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल ने 'नजूल की जमीन' कैसे और क्यों खरीदी? एक उदाहरण सामने आया है कि 2.92 करोड़ रुपए की नजूल-भूमि 23-24 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी गई? नजूल की जमीन सरकारी संपत्ति होती है, जो राज्य सरकार को सौंपी जाती है। यह जमीन लीज, पट्टे पर तो दी जा सकती है, लेकिन इसे बेचा-खरीदा नहीं जा सकता।

कुछ अलग

शीशे का महल

उसने बहुत सारे ख्वाब देखे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे दिखाए गए हैं। वह सपनों में रहते हुए अपनी, देश और पूरे विश्व की हर संभावना को उज्ज्वल होते देखने लगा है। ये सपने कई बार बिना संभावना और क्षमता के भी उसे इतना ऊंचा ले जाते कि न आकाश और न ही खजूर पर लटकने का भय बचा है। सपने उसे व देश को हमेशा महानतम बना देते और अब वह हर उम्मीद या प्रयास को ख्वाब में पूरा कर लेता है। लोग मान चुके हैं कि वह 'सपनजीवी' है, लेकिन एक दिन वह सपने में शीश महल के भीतर राजा बना घूमने लगा। उसे लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है कि एक वही बड़े दिलवाला है और शीशे के महल का सही से उपयोग कर सकता है। लोग उसे देख रहे थे। वह राजसी मुद्रा में अभिवादन स्वीकार करता, लेकिन देखने वाले ही उसे कम होते दिखाई दे रहे थे। उसे पहली बार सपने से मालूम हुआ कि शीशमहल की आंखें कमजोर होती हैं। वैसे यह आंखों का फर्क भी हो सकता है कि सपने कैसे दिखें, और शीशे का भी कि इसके ऊपर गर्द कितनी चढ़े। कुछ परिस्थितियों में हम भली चंगी आंखों पर भरोसा नहीं करते, कई बार देखकर भी यह नहीं मानते हैं कि हम देख रहे हैं। आजादी के बाद हमने जिस स्वतंत्रता से स्वतंत्रता को देखना शुरू किया, वहां हमारी आंखें थी ही कहां। हम कई बार राजनीति की बड़ी या चौड़ी बहस देखते हैं, लेकिन वहां आंखें अक्सर छोटी होती हैं। इस बहस का नतीजा आज तक नहीं निकला कि नेहरु ने देश की आंखें बड़ी की या वाजपेयी ने या आज तक बड़ी हो रही हैं। वैसे आजकल टीवी चैनलों के बड़ी आंखों वाले एंकरों की वजह से हम अपनी आंखें छोटी करने पे उतारू हैं।

दल-बदल विरोधी कानून भारतीय लोकतंत्र में स्थिरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की जटिल बहस को जन्म देता है

दल-बदल विरोधी कानून : स्थिरता की गारंटी या लोकतांत्रिक विवेक पर अंकुश?

डॉ. प्रियंका सौरभ

संसद और विधानसभाएँ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा इन संस्थाओं की स्थिरता लोकतांत्रिक शासन के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। किंतु भारतीय राजनीति में लंबे समय तक दल-बदल की प्रवृत्ति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी। व्यक्तिगत लाभ, मंत्री पद, आर्थिक प्रलोभन अथवा राजनीतिक अवसरवाद के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि बार-बार अपनी निष्ठा बदलते रहे, जिससे सरकारें गिरती रहीं और जनादेश का अपमान होता रहा। इसी समस्या के समाधान के लिए 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों को राजनीतिक दलों के प्रति अनुशासित बनाए रखना तथा सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करना था। हालाँकि समय के साथ यह कानून स्वयं बहस का विषय बन गया है।

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार केवल नियमित चुनाव नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और जनादेश के प्रति निष्ठा भी है। संसद और विधानसभाएँ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा इन संस्थाओं की स्थिरता लोकतांत्रिक शासन के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। किंतु भारतीय राजनीति में लंबे समय तक दल-बदल की प्रवृत्ति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी। व्यक्तिगत लाभ, मंत्री पद, आर्थिक प्रलोभन अथवा राजनीतिक अवसरवाद के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि बार-बार अपनी निष्ठा बदलते रहे, जिससे सरकारें गिरती रहीं और जनादेश का अपमान होता रहा। इसी समस्या के समाधान के लिए 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों को राजनीतिक दलों के प्रति अनुशासित बनाए रखना तथा सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करना था। हालाँकि समय के साथ यह कानून स्वयं बहस का विषय बन गया है। एक पक्ष इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार और अवसरवाद के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा कवच मानता है, जबकि दूसरा पक्ष तर्क देता है कि यह सांसदों और विधायकों की स्वतंत्र सोच तथा अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता है। इस प्रकार दल-बदल विरोधी कानून भारतीय लोकतंत्र में स्थिरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की जटिल बहस को जन्म देता है। दल-बदल की समस्या स्वतंत्रता के बाद के दशकों में तेजी से बढ़ी। 1967 के आम चुनावों के बाद अनेक राज्यों में विधायकों ने बड़े पैमाने पर दल बदले। उस समय "आया राम, गया राम" शब्दावली भारतीय राजनीति का प्रतीक बन गई। हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में कई बार दल बदलने की घटना ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप सरकारें अस्थिर हुईं, राजनीतिक नैतिकता कमजोर हुई और जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम होने लगा। इसी पृष्ठभूमि में दल-बदल को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई। दसवीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। स्वतंत्र सदस्य किसी दल में शामिल नहीं हो सकता और मनोनीत सदस्य भी निर्धारित अवधि के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। इस कानून के समर्थकों का तर्क है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले, इसने सरकारों की स्थिरता को मजबूत किया है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ के लिए बार-बार दल बदलते रहें, तो सरकारें निरंतर संकट में रहेंगी और प्रशासनिक निर्णय प्रभावित

होंगे। दल-बदल विरोधी कानून ने इस प्रवृत्ति पर कुछ हद तक अंकुश लगाया है। दूसरे, यह कानून राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। अक्सर दल-बदल मंत्री पद, धन अथवा अन्य लाभों के लिए किया जाता है। ऐसे अवसरवादी व्यवहार से लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचती है। कानून का भय कम से कम खुले तौर पर होने वाले राजनीतिक सौदों को सीमित करता है। तीसरे, यह जनादेश की रक्षा करता है। मतदाता प्रायः किसी उम्मीदवार को उसके दल, विचारधारा और चुनावी घोषणापत्र के आधार पर चुनते हैं। यदि निर्वाचित सदस्य बाद में दल बदल लेता है, तो वह मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुँचाता है। इसलिए दल-बदल विरोधी कानून मतदाताओं की अपेक्षाओं की रक्षा का माध्यम माना जाता है। चौथे, यह राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि दल के सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट रहें। यदि प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार मतदान करे, तो सरकार का संचालन कठिन हो सकता है। इन सकारात्मक पक्षों के बावजूद दल-बदल विरोधी कानून की आलोचना भी व्यापक रूप से होती रही है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता को सीमित करता है। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, केवल राजनीतिक दलों के एजेंट नहीं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी विधेयक या नीति पर अपने विवेक, अनुभव और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। किंतु व्हिप की बाध्यता के कारण उन्हें दल के निर्देशों का पालन करना पड़ता है, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। यह स्थिति लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करती है। संसद और विधानसभाओं का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी देना नहीं, बल्कि गहन चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से बेहतर नीतियों का निर्माण करना है। जब सदस्य स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने से डरते हैं, तो बहस की गुणवत्ता प्रभावित होती है और विधायिका की भूमिका सीमित हो जाती है। कानून की दूसरी प्रमुख कमजोरी अध्यक्ष या सभापति की भूमिका से जुड़ी है। अयोग्यता संबंधी निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है, जो सामान्यतः किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि अध्यक्षों ने राजनीतिक हितों के अनुसार निर्णय लेने में देरी की या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। इससे कानून की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है। तीसरी आलोचना यह है कि कानून ने दल-बदल को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके स्वरूप को बदल दिया है। पहले व्यक्तिगत स्तर पर दल-बदल होता था, जबकि अब सामूहिक इस्तीफों और पुनर्निर्वाचन के माध्यम से सरकारें गिराई जाती हैं। हाल के वर्षों में कई राज्यों में विधायकों ने पहले इस्तीफा दिया और बाद में दूसरे दल में शामिल होकर पुनः चुनाव लड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि कानून की भावना को दरकिनार करने के नए तरीके खोज लिए गए हैं। चौथा, यह कानून राजनीतिक दलों के नेतृत्व को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी व्हिप का पालन करना सदस्यों के लिए अनिवार्य हो जाता है। इससे आंतरिक लोकतंत्र कमजोर पड़ता है और पार्टी के भीतर असहमति व्यक्त करने की गुंजाइश कम हो जाती है। परिणामस्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं की बजाय पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देने लगते हैं। इन आलोचनाओं को देखते हुए विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञों ने सुधारों का सुझाव दिया है। विधि आयोग, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग तथा कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि दल-बदल विरोधी कानून का दायरा सीमित किया जाए। उनका मानना है कि व्हिप केवल उन मामलों में लागू होना चाहिए जो सरकार के अस्तित्व से सीधे जुड़े हों, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विनियोग विधेयक या अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय विषय। सामान्य विधायी मामलों में सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी प्रकार अयोग्यता संबंधी निर्णय अध्यक्ष के बजाय किसी स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण अथवा निर्वाचन आयोग को सौंपने का सुझाव भी दिया गया है। इससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की है और समयबद्ध निपटान की आवश्यकता पर बल दिया है। अन्य लोकतांत्रिक देशों का अनुभव भी इस बहस को रोचक बनाता है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संसदीय लोकतंत्रों में दलगत अनुशासन तो है, किंतु भारत जैसी कठोर अयोग्यता व्यवस्था नहीं है। वहाँ सांसद कई बार पार्टी लाइन से अलग मतदान करते हैं, फिर भी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। इससे संसदीय बहस अधिक स्वतंत्र और जीवंत बनी रहती है। दूसरी ओर भारत जैसी विविधतापूर्ण और गठबंधन-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका अधिक रहती है।

देश दुनीया से

सुरक्षा की जीत, गरिमा की हार? नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का दोहरा चेहरा

21 जून 2026 को नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा समाप्त हुई। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते लाखों विद्यार्थियों के चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा बोझ भी झलक रहा था। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में आयोजित किया गया। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों, 95 हजार परीक्षा कक्षों, 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरों, 51 हजार जैमरों, हजारों बायोमेट्रिक कर्मचारियों और कड़ी फ्रिस्किंग के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पेपर लीक की आशंकाएं लगभग समाप्त रहीं और परिणामों पर विश्वास बहाल होने की उम्मीद जगी। इसके लिए एनटीए और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस सफलता के बीच एक सवाल खड़ा है—क्या निष्पक्षता की यह कीमत हमारी युवा पीढ़ी की गरिमा और मानसिक शांति से वसूली जानी चाहिए? पिछले वर्षों में बार-बार हुए पेपर लीक कांडों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई थी। मई 2026 की घटना के बाद सरकार और एनटीए ने पूरे तंत्र को लगभग रीसेट कर दिया। प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर उनके परिवहन तक अभूतपूर्व गोपनीयता बरती गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्थानों पर भारतीय वायुसेना की सहायता से प्रश्न-पत्र पहुंचाए गए, जीपीएस ट्रैकिंग, पुलिस एस्कॉर्ट और एआई आधारित निगरानी तंत्र सक्रिय किए गए। राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग हुई। हजारों पर्यवेक्षक, साइबर निगरानी दल और खुफिया एजेंसियों का त्रिस्तरीय सुरक्षा नेटवर्क परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर रखे रहा। यह व्यवस्था किसी शैक्षणिक आयोजन से अधिक एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान जैसी प्रतीत होती थी। इन उपायों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। लाखों विद्यार्थियों को भरोसा मिला कि इस बार उनकी मेहनत संगठित नकल या पेपर लीक के कारण व्यर्थ नहीं जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े माता-पिता को भी संतोष था कि उनके बच्चों का भविष्य किसी अपराधी गिरोह या भ्रष्ट नेटवर्क के हाथों बंधक नहीं बनेगा। लंबे समय से अपेक्षित विश्वास बहाली की दिशा में यह एक

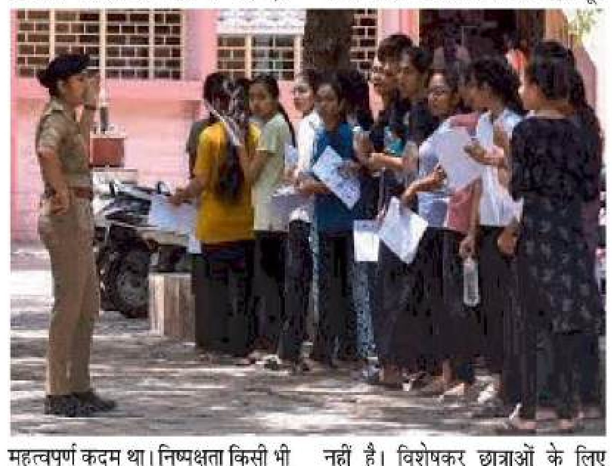

महत्वपूर्ण कदम था। निष्पक्षता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है और उसे बचाने के लिए कठोर कदमों का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है। किंतु हर सफलता कुछ ऐसे प्रश्न भी छोड़ जाती है जिन्हें केवल आंकड़ों और प्रशंसाओं से ढंका नहीं जा सकता। सबसे बड़ा प्रश्न उस अनुभव का है जिससे विद्यार्थी गुजरे। आधार आधारित फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट सत्यापन, जेबों, कानों, जूतों और यहां तक कि कपड़ों की चेन, जिप तथा धागों तक की जांच—यह सब उस युवा पीढ़ी के साथ हुआ जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी। 38,795 फ्रिस्किंग कर्मी और 48,448 बायोमेट्रिक कर्मचारी व्यवस्था की आवश्यकता रहे होंगे, लेकिन विद्यार्थियों के मन में यह अनुभव भी दर्ज हुआ कि उन पर पहले संदेह किया गया, बाद में विश्वास। कई अभ्यर्थियों ने स्वयं को अपराधियों की तरह टटोला जाता महसूस किया। यह भावना किसी परीक्षा की सफलता का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर छात्राओं के लिए फ्रिस्किंग कई बार असहजता और तनाव का कारण बनी। यद्यपि महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, फिर भी मानसिक दबाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। माता-पिता दूर खड़े अपने बच्चों को डिजिटल और भौतिक निगरानी के घेरे में प्रवेश करते देखते रहे। शिक्षा का मंदिर कई स्थानों पर सुरक्षा चौकी जैसा दिखाई देने लगा। यह दृश्य केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस सामाजिक अविश्वास का भी प्रतीक है जो धीरे-धीरे संस्थाओं और नागरिकों के बीच बढ़ता जा रहा है। जब एक छात्र परीक्षा देने से पहले स्वयं को संदिग्ध साबित होने से बचाने की प्रक्रिया से गुजरता है, तब कहीं न कहीं शिक्षा का मूल उद्देश्य भी आहत होता है। दरअसल समस्या का मूल कारण विद्यार्थी नहीं हैं। समस्या उस व्यवस्था में है जिसने वर्षों तक पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों को पनपने दिया। यदि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत होती, तो शायद इतनी कठोर सुरक्षा की आवश्यकता न पड़ती। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली की ओर संक्रमण, उन्नत डिजिटल सुरक्षा उपाय तथा एनटीए में संरचनात्मक सुधार लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस बार की सफलता सिद्ध करती है कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन यदि सुधार केवल सुरक्षा तक सीमित रहेगा और मूल समस्याएं जस की तस रहेंगी, तो हर वर्ष विद्यार्थियों को इसी प्रकार की कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देश को अब तय करना होगा कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली कैसी हो। क्या हम हर वर्ष युद्ध जैसी तैयारियां करेंगे, या ऐसे तकनीकी और संस्थागत सुधार विकसित करेंगे जिनसे सुरक्षा और सम्मान दोनों साथ चल सकें? फ्रिस्किंग को अधिक संवेदनशील और कम अपमानजनक बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया को चरणबद्ध, डिजिटल और लीक-प्रूफ बनाया जा सकता है। सुरक्षा का उद्देश्य भय नहीं, विश्वास पैदा करना होना चाहिए। यदि कोई व्यवस्था निष्पक्ष तो हो जाए, पर उसमें मानवीय गरिमा खो जाए, तो वह अधूरी सफलता ही कहलाएगी। नीट-2026 की पुनर्परीक्षा भारत की परीक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

आप का नजरीया

लेबनान की आग ने अमेरिका-ईरान वार्ता पर डाले साए

लगभग चार महीनों से पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच हुआ प्रारंभिक समझौता (एमओयू) अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता से पहले ही यह स्पष्ट हो गया है कि समझौते का सबसे संवेदनशील मुद्दा-लेबनान में जारी इज़रायली सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़ा युद्धविराम-अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास फिर से उभरता दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-सूत्रीय समझौते की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस ढांचे का उद्देश्य परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दों और होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की सुरक्षा पर आगे की बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना था। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में औपचारिक वार्ता और आगे की बातचीत प्रस्तावित थी। लेकिन घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष फिर भड़क उठा। दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम के बावजूद रॉकेट हमले, जवाबी हवाई हमले और सीमा पर सैन्य गतिविधियां जारी रहीं। इन घटनाओं ने उस बुनियादी शर्त को कमजोर कर दिया जिस पर ईरान ने आगे की वार्ता के लिए सहमति जताई थी। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि यदि लेबनान में हिंसा नहीं रुकती तो कूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाना कठिन होगा। यही कारण है कि वार्ता की समय-सीमा और स्वरूप को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा को पहले स्थगित किया गया था और बाद में नई बैठकों की तैयारी शुरू हुई। दूसरी ओर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी स्पष्ट संकेत दिए कि लेबनान का मुद्दा उनके लिए केवल एक क्षेत्रीय प्रश्न नहीं बल्कि भरोसे की कसौटी है। मौजूदा स्थिति में स्विट्जरलैंड एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है। ज्यूरिख और अन्य स्विस स्थलों पर अमेरिकी, ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी प्रतिनिधियों की गतिविधियां तेज हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसने पहले भी संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराया था। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा आयाम होर्मुज जलडमरूमध्य भी है। ईरान की ओर से समय-समय पर जलमार्ग बंद करने की चेतावनी और अमेरिका द्वारा समुद्री यातायात बनाए रखने की प्रतिबद्धता ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान संकट समझौते के पूर्ण विफल होने का संकेत नहीं है। अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्षों ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया है कि वे वार्ता का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि लेबनान में संघर्ष जारी रहने पर किसी भी बड़े समझौते को आगे बढ़ाना बेहद कठिन होगा। कूटनीति तभी सफल हो सकती है जब जमीनी हालात उसमें सहयोग करें। इस समय दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड पर टिकी हैं। वहां होने वाली बातचीत केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

ईरानी नेतृत्व का कहना है कि यदि लेबनान में हिंसा नहीं रुकती तो कूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाना कठिन होगा। यही कारण है कि वार्ता की समय-सीमा और स्वरूप को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा को पहले स्थगित किया गया था और बाद में नई बैठकों की तैयारी शुरू हुई। दूसरी ओर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी स्पष्ट संकेत दिए कि लेबनान का मुद्दा उनके लिए केवल एक क्षेत्रीय प्रश्न नहीं बल्कि भरोसे की कसौटी है। मौजूदा स्थिति में स्विट्जरलैंड एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है। ज्यूरिख और अन्य स्विस स्थलों पर अमेरिकी, ईरानी, पाकिस्तानी और क़तरी प्रतिनिधियों की गतिविधियां तेज हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसने पहले भी संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराया था। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा आयाम होर्मुज जलडमरूमध्य भी है। ईरान की ओर से समय-समय पर जलमार्ग बंद करने की चेतावनी और अमेरिका द्वारा समुद्री यातायात बनाए रखने की प्रतिबद्धता ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा।

दृष्टि कोण

टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देती सरकार

यकीनन इस समय सरकार देश के 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले और करीब 174 अरब डॉलर के बाजार आकार के टेक्सटाइल्स सेक्टर को मजबूती देने के लिए रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ रही है। सरकार ने एक जून से पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित हो रहे टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने और निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आगामी पांच माह के लिए कपास आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से माफ कर दिया है। सरकार लगातार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। हाल ही में लागू किए गए नए श्रम कानूनों से टेक्सटाइल सेक्टर को जोरदार बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के विकास के लिए पीएम मित्र पार्क मील का पत्थर हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रावधानों का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। साथ ही पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में सुधार के लिए उठाए गए बहुआयामी कदम टेक्सटाइल सेक्टर को लाभान्वित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस परिदृश्य के मद्देनजर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की रेटिंग बढ़ाई है। इनवेस्टमेंट इनफॉरमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का आउटलुक 'नेगेटिव' से बढ़ाकर 'स्टेबल' कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक जून से भारत और ओमान के बीच सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) लागू हुआ है। इस समझौते के तहत ओमान ने भारत के टेक्सटाइल सहित 99 प्रतिशत से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क पूरी तरह से शून्य कर दिया है। इस शून्य शुल्क व्यवस्था के कारण, ओमान में भारतीय कपड़ों की लागत कम होगी, जिससे आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात में भारी उछाल आने की उम्मीद है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ओमान को लगभग 930 रुपए का टेक्सटाइल निर्यात किया था। यह पांच वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इसी तरह एफटीए वाले अन्य देशों में जीरो या

लगभग जीरो ड्यूटी एक्सेस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रहे एफटीए से टेक्सटाइल निर्यात में भारी उछाल आया है। साथ ही आगामी महीनों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के क्रियान्वयन से इन देशों को भारत से तेजी से टेक्सटाइल निर्यात बढ़ेगा। खासतौर से यूरोप के 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर अमल शुरू होने के दो-तीन वर्षों में ही यूरोपीय संघ को भारत से करीब 20 अरब डालर तक का टेक्सटाइल निर्यात बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इन दिनों अमरीका के साथ जिस द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके तहत भारत को अमरीका में धागे और कपास से बने कपड़ों पर भारी शुल्क छूट हासिल होगी और टेक्सटाइल निर्यात ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देने के मद्देनजर पिछले माह 9 मई से पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू की गई चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन चार श्रम संहिताओं- मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत नए सरल श्रम कानून टेक्सटाइल उद्योग-कारोबार की मजबूती और विकास की नई संभावनाओं को आकार देने के मद्देनजर महत्वपूर्ण हैं। नए श्रम कानूनों से व्यापार समझौतों का प्रभावी रूप से लाभप्रद क्रियान्वयन होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही का सशक्त माध्यम : सत्येंद्र कुमार

वाराणसी, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पिरामल फाउंडेशन की ओर से विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म एआई सचिव जी का शुभारंभ सोमवार को किया गया। कचहरी स्थित आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा तथा प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने पोस्टर जारी करते हुए इसकी शुरूआत की। इस अवसर पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि एआई सचिव जी के माध्यम से ग्राम पंचायतों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, शासन की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सूचनाएं लिखित एवं मौखिक रूप में प्राप्त की जा सकेंगी। साथ ही बैठकों की कार्यवाही, रिपोर्ट तैयार करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को सरल, त्वरित और समयबद्ध बनाने में भी यह प्लेटफॉर्म सहायक सिद्ध होगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को तकनीकी सहायता, सरकारी योजनाओ की जानकारी मिलेगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सुविधा होगी। जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि पंचायतों में आधुनिक तकनीक का समावेश समय की आवश्यकता है। एआई सचिव जी के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को त्वरित जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष रकेश सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से पंचायतों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में फाउंडेशन की कोर टीम के सदस्य विंग कमांडर जैनेंद्र कुमार पाठक, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर बशारत, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर संतोष सिंह तथा प्रोग्राम मैनेजर चन्द्रशेखर ने एआई सचिव जी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं अन्य आवश्यक जानकारियों तक त्वरित पहुंच उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम के दौरान एआई सचिव जी का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया।

इसमें बताया गया कि यह प्लेटफॉर्म पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने, बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में तत्काल सहायता प्रदान करेगा। उपस्थित ग्राम प्रधानों एवं अधिकारियों ने इसे सरल, उपयोगी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर संतोष सिंह ने की, जबकि कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं समन्वय में साक्षी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम प्रधान, प्रधान संघ के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, गांधी फेलो, फाउंडेशन की टीम सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी ने फिरोजाबाद को दी 658 करोड़ की 81 परियोजनाओं की सौगात, कहा–डबल इंजन को वोट देने का परिणाम है विकास

फिरोजाबाद, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फिरोजाबाद में कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में वन जिला वन माफिया हुआ करते थे लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के रूप में जानी जाती है। उन्होंने फिरोजाबाद की जनता से इसी तरह भाजपा को समर्थन करने का भी आवाहन किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को विकास का पर्याय बताते हुए टूंडला एवं शिकोहाबाद विधानसभा की 658 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फिरोजाबाद में टूंडला विधानसभा के गांव उसायनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नवनिर्मित 568 भवनों के लाभार्थियों को आवासों की चाबी प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने टूंडला एवं शिकोहाबाद विधानसभा की 658 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया तथा अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के उद्यमियों एवं श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि आज विश्व पटेल पर फिरोजाबाद को लोकल से ग्लोबल बनाने में इनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से ही फिरोजाबाद को 568 करोड़ कि परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है लेकिन इसका श्रेय फिरोजाबाद की जनता को जाता है, क्योंकि जब आप अपना वोट सही जगह करते है एवं ईवीएम का सही बटन दबाते हैं तो फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल बनती है। उन्होंने कहा कि आज फिरोजाबाद के कांच उद्योग ने चीन को पछाड़ दिया है पहले दीपावली, होली, रक्षाबंधन किसी की पर्व पर या किसी अतिथि को चीन से बने उत्पादन उपहार में दिए जाते थे क्योंकि यही उत्पाद मार्केट में मिलते थे लेकिन फिरोजाबाद के कांच कारीगरों ने यह नई तकनीक तैयार की। कांच के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहुंचाये। अब हर पर्व पर या किसी अतिथि के आने पर कांच की सुन्दर प्रतिमा जब उपहार में दी जाती है तो अतिथि भी खुश हो जाता है। उन्होंने कहा कि राम दरबार, गणेश, भगवान शिवा, बुद्ध आदि की सुन्दर सुन्दर प्रतिमाएं कांच से बनती है यह श्रमिकों की कला है और यह कला पहले भी थी लेकिन 2017 से पूर्व श्रमिकों की इस कला को प्रोत्साहन नहीं मिला। कारखाने को गैस की आपूर्ति नहीं मिली। इसी कारण फिरोजाबाद 2017 से पहले लोकल से ग्लोबल नहीं बन सका। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के एजेंडे में विकास नहीं है। सपा का काम समाज को बांटना, समाज की एकता को खत्म करना, गुंडागर्दी को प्रोत्साहन करना, विकास योजना में रोड़ा अटकना, किसी पर्व से पहले उस पर्व के उत्सव को उपद्रव में बदलना यही सपा का काम है। 2017 से पहले बन डिस्ट्रिक वन माफिया हुआ करते थे। हर जिले में एक चिन्हित माफिया होता था जिसका काम गरीबों की और सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, गुंडागर्दी करना व्यापारियों से चौथ वसूली करना और प्रदेश में अराजकता पैदा करना होता था लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा अब यूपी में सब चंगा है। त्योहारों व पर्व पर उपद्रव नहीं उत्सव होता है। आरोप लगाया कि सपा सरकार ने कावंड़ यात्रा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सवों को भी रोकने का काम किया। गरीबों को राशन नहीं मिलता था, बिजली भी नहीं आती थी क्योंकि कांग्रेस, सपा व बसपा के लोग अंधेरे में रहने की आदी थे क्योंकि अंधेरे में ही डकैती पड़ती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सभी को बिजली, पानी, शिक्षा स्वास्थ आदि की सुविधाएं मिल रही है तथा सभी योजनाओं को लाभ भी मिल रहा है। इससे पूर्व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। प्रदेश सरकार की पहचान पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा की सरकार के नाम से है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री विधायक प्रेमपाल धनगर और मनीष असीजा ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर महापौर कामिनी राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सुमित प्रताप, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के साथ पार्टी के पूर्व विधायक, नेता आदि मौजूद रहे।

एसपी ने सराहनीय कार्य करने वाले यूपी 112 के 8 कर्मियों को किया सम्मानित

हमीरपुर, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) मृगांग शेखर पाठक ने सोमवार को यूपी-112 के उन आठ पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान त्वरित, मानवीय एवं सराहनीय कार्य करते हुए जरूरतमंदों की सहायता कर पुलिस की संवेदनशील छवि को मजबूत किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने विभिन्न घटनाओं में तत्परता दिखाते हुए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जिनमें थाना मौदहा क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची के मिलने की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची से पूछताछ की गई तथा उसके परिजनों को बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया। इसी तरह थाना जरिया क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहांड पहुंचाकर समय से उपचार उपलब्ध कराया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। थाना राठ क्षेत्र में मोटरसाइकिल एवं ई-रिक्शा की आमने-सामने हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंचाकर उपचार कराकर जान बचाई गई है। इन सराहनीय एवं मानवीय कार्यों के लिए पायलट होमगार्ड 526 इस्माइल, कमाण्डर आरक्षी विकास कुमार, पायलट आरक्षी संजेश कुमार, सब कमाण्डर सत्यप्रकाश, कमाण्डर आरक्षी आसिफ शेख, पायलट आरक्षी मो. फिरोज, सह कमाण्डर आरक्षी रनवीर, कमाण्डर मुख्य आरक्षी अतुल कुमार को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि उक्त पुलिस कर्मियों की तत्परता, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवीय संवेदनशीलता पुलिस विभाग की उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचायक है। ऐसे कार्यों से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास, सुरक्षा एवं सम्मान की भावना और अधिक सुदृढ़ होती है तथा समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित होता है।

भारतेंदु नाट्य अकादमी में पढ़ाई करेंगे बलिया के ट्विंकल और शुभम

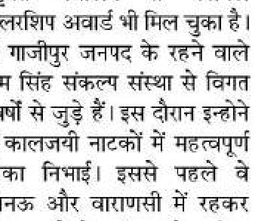

बलिया, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दो उदीयमान कलाकारों का चयन भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में परास्नातक के लिए हुआ है। साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था संकल्प से जुड़े इन दो कलाकारों का चयन होने कला जगत में खुशी की लहर है। भारतेंदु नाट्य अकादमी में प्रवेश हेतु कई चरणों से गुजरना होता है। इसमें अखिल भारतीय स्तर पर केवल 20 सीट है, जिसमें संकल्प संस्था के दो रंगकर्मियों ट्विंकल गुप्ता और शुभम सिंह द्वारा स्थान हासिल करना चर्चा का विषय है। ट्विंकल विगत 10 वर्षों से संकल्प संस्था से जुड़ कर रंगकर्म कर रही हैं। दर्जनों नाटकों में अभिनय व निर्देशन कर चुकी ट्विंकल इससे पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी सेंटर से इंडियन क्लासिकल थियेटर में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स कर चुकी हैं। ट्विंकल को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से नेशनल स्कालरशिप अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं गाजीपुर जनपद के रहने वाले शुभम सिंह संकल्प संस्था से विगत दो वर्षों से जुड़े हैं। इस दौरान इन्होने कई कालजयी नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले वे लखनऊ और वाराणसी में रहकर थियेटर करते थे। संकल्प के सचिव रंग निर्देशक व प्रशिक्षक आशीष त्रिवेदी ने दोनों कलाकारों को संस्था की ओर से बधाई दी है।

रायबरेली में लगे विवादित पोस्टर, सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा

रायबरेली, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सोमवार की सुबह शहर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी करते हुए पोस्टर लगाये गए है। इससे आक्रोशित सपा कार्यकताओं ने कोतवाली में हंगामा करते हुए कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। सोमवार की सुबह शहर में लगे कई पोस्टरों से सियासी तापमान बढ़ गया। पोस्टर वॉर की खबर फैली, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकताओं में भारी नाराजगी फैल गई। कई कार्यकर्ता शहर कोतवाली पहुंच गए और वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजी वीरेंद्र यादव का कहना है जानबूझकर ऐसे विवादित होर्डिंग लगाये गए हैं ताकि समाज में जातीय तनाव पैदा किया जा सके और राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

रांची-सासाराम इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला मार्ग

पलामू, (हि.स.)। दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) ने धनबाद मंडल के सीपीडीआर-बरवाडीह-महुआमिलान रेलखंड में तीसरी अप लाइन के कमीशनिंग कार्य के लिए 23 जून से 27 जून 2026 तक नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किए जाने की घोषणा की है। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्री-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 17 जून से 22 जून तक तथा नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य 23 जून से 27 जून तक चलेगा। इस दौरान पलामू और आसपास के क्षेत्रों के रेल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। सबसे अधिक असर दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन संख्या 18635 रांची-सासाराम एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 18636 सासाराम-रांची एक्सप्रेस को 23, 24, 25, 26 और 27 जून 2026 को रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन पलामू, गढ़वा और रोहतास जिले के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क साधन मानी जाती है। इसके अलावा बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन, बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन, बरवाडीह-चोपन, गोमो-बरवाडीह तथा डेहरी ऑन सोन-बरवाडीह सहित कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का परिचालन भी निर्धारित तिथियों में रद्द रहेगा। वहीं, हटिया-नई दिल्ली, रांची-नई दिल्ली, आनंद विहार-हटिया, हावड़ा-जबलपुर, टाटा-जम्मूतवी और धनबाद-भोपाल सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा रेलवे ने 23 जून से 27 जून तक बरवाडीह स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को भी वापस लेने का निर्णय लिया है। इस अवधि में यात्रियों को डाल्टनगंज अथवा महुआमिलान स्टेशन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस ऐप, हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा संबंधित स्टेशन से प्राप्त करने की अपील की है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली, सूचना पट, एसएमएस और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

पूर्व सांसद बागुन सुम्बरुई की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

पश्चिमी सिंहभूम, (हि.स.)। झारखंड आंदोलन के पुरोधा और पूर्व सांसद स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई की पुण्यतिथि पर सोमवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके संघर्षमय जीवन, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति योगदान को याद किया गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि बागुन सुम्बरुई केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि झारखंडी अस्मिता, आदिवासी स्वाभिमान और जनसंघर्ष की मजबूत आवाज थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुम्बरुई ने अपना पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि बागुन सुम्बरुई किसानों, मजदूरों, वंचितों और शोषितों की आवाज बनकर हमेशा संघर्ष करते रहे। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने झारखंड और विशेषकर कोल्हान क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया। झारखंड आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने और आदिवासी समाज को राजनीतिक, सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार दिलाने में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। त्रिशानु राय ने कहा कि बागुन सुम्बरुई का सादा जीवन, स्पष्ट विचार और जनता के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मौके पर सोशल मीडिया जिला चेयरमैन रवि कच्छप, विक्रमादित्य सुंडी, अजय कुमार, बिक्रम बिरुली, मो. ईस्लाम, बिजय जारिका, शिव दास, सुरज नायक, सुशील दास सहित अन्य उपस्थित थे।

वरिष्ठ दलील लेखक भवतोष राय का निधन, चाईबासा में शोक की लहर

पश्चिमी सिंहभूम,(हि.स.)। चाईबासा शहर के बांधपाड़ा निवासी एवं वरिष्ठ दलील लेखक भवतोष राय का सोमवार सुबह जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही चाईबासा सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। भवतोष राय लंबे समय से विधिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे और दलील लेखक के रूप में उनकी एक अलग पहचान थी। अपने सरल स्वभाव, सौम्य व्यवहार और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण वे अधिवक्ताओं, मुवक्किलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। विधिक क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन पर अधिवक्ता समुदाय, सामाजिक संगठनों तथा शहर के गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। कई लोगों ने इसे चाईबासा के सामाजिक और विधिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उनके निधन की सूचना मिलते ही शुभचिंतकों और परिचितों का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, भवतोष राय अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके बड़े पुत्र पार्थ सारथी राय शिक्षक हैं, जबकि छोटे पुत्र सव्यसाची राय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। उनकी पुत्रवधू उपमा राय चाईबासा नगर परिषद की वार्ड पार्षद हैं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। परिजनों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज चाईबासा स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है।

संस्कार भारती द्वारा सुर वंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कला साधकों ने दी प्रस्तुति

सारण, (हि.स.)। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कला एवं साहित्य के क्षेत्र में समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती, सारण इकाई द्वारा सुर वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, दर्शन नगर, छपरा के सभागार में आयोजित यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जिसमें सुर, ताल और विधाओं का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विनोद मिश्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग व्यवस्था प्रमुख ओम प्रकाश गुप्ता, संस्कार भारती उत्तर बिहार के महामंत्री सुरभित दत्त, छपरा की विधायक छोटी कुमारी, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव तथा प्रधानाचार्य विनोद कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात संस्कार भारती के पारंपरिक ध्येय गीत की प्रस्तुति मंजू कुमारी एवं अन्य सहयोगियों द्वारा की गई, जिससे कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत हुई। उत्तर बिहार प्रांतीय कला टोली के संयोजक चंद्र मिश्रा ने विषय प्रवेश कराते हुए जीवन में संगीत और कला के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंच का संचालन भंवर किशोर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक मोहित कुमार सिंह ने बताया कि इस विश्व संगीत दिवस पर मां सरस्वती के उपासकों और कला साधकों ने अपनी अनूठी प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों ने कथक नृत्य की मनमोहक मुद्राओं, एकल गीत, समूह गीत और एकल वाद्य यंत्रों की सुमधुर जुगलबंदी से सभागार में मौजूद सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त, काव्य पाठ सत्र में जुटे कवियों द्वारा वीर रस और हास्य-व्यंग्य की प्रस्तुतियां दी गईं, जिसे श्रोताओं की खूब सराहना मिली। इस अवसर पर कला, संगीत और काव्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले प्रतिभावान कलाकारों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में मुख्य रूप से आदित्य सोनी, उदय श्रीवास्तव, सुरेश चौबे, अनिशा कुमारी, विवेक समदर्शी, विश्वनेक समदर्शी, अमरेंद्र सिंह, राजनंदिनी, ललितेश गर्ग, राकेश कुमार सिंह, कौशलेश गर्ग, सौम्या कुमारी, उदय नारायण सिंह, सुप्रशात कुमार सिंह, शालिनी कुमारी, उदय कुमार, प्रेम गुप्ता तथा मेहंदी शॉ इत्यादि अन्य दर्शक, श्रोता उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन संपूर्ण वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ।

जिलाधिकारी के तौर पर अलंकृता पांडेय ने ग्रहण किया पदभार

भागलपुर, (हि.स.)। भागलपुर के जिलाधिकारी के तौर पर अलंकृता पांडेय ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने उन्हें पदभार सौंपा। उल्लेखनीय है कि अलंकृता पांडेय साल-2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। अलंकृता पांडेय अपनी प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी हालिया ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश के बाद भागलपुर में नए प्रशासनिक युग की शुरूआत होने जा रही है। इसके पूर्व अलंकृता पांडे जहानाबाद जिले में जिलाधिकारी के रूप में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रही थीं। अब उनके कंधों पर सिल्क सिटी भागलपुर के विकास और कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होगी। आईएएस अलंकृता पांडे ने जहानाबाद की जिलाधिकारी रहते हुए जनहित के कई बड़े फैसले लिए और विकास कार्यों को धरातल पर उतारा। प्रशासनिक दक्षता और जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाली अलंकृता पांडे अब भागलपुर जिले के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं को नई गति देंगी। भागलपुर जैसे बड़े और ऐतिहासिक जिले में उनकी नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली अलंकृता पांडे बचपन से ही मेधावी रही हैं। उन्होंने देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सर्विस परीक्षा में अपने शानदार प्रदर्शन से ऑल इंडिया 85वीं रैंक हासिल की थी। उनकी इस सफलता के बाद उन्हें 2016 बैच के आईएएस अधिकारी के रूप में देश सेवा का मौका मिला। एक्यूअलंकृता पांडे के कैडर बदलने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद उन्हें प्रारंभिक रूप से पश्चिम बंगाल कैडर आवंटित किया गया था। लेकिन जीवन के सफर में एक नया मोड़ आया और उनका विवाह बिहार कैडर के ही आईएएस अधिकारी अंशुल अग्रवाल से हुआ। शादी के बाद नियमानुसार उनका इंटर-कैडर ट्रांसफर हुआ और वे पश्चिम बंगाल से बिहार कैडर में आ गईं। तब से वे बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा रही हैं। भागलपुर जिला प्रशासन में इस नए बदलाव के बाद स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध जनों में काफी उत्साह है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ट्रैफिक व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसे कई मोर्चों पर काम चल रहा है।

भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 147 बोतल नेपाली शराब की जब्त, तस्कर फरार

अररिया, (हि.स.)। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 52वीं वाहिनी ने 147 बोतल नेपाली शराब जब्त की है। यह कार्रवाई बीती देर रात सिकटी क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा के समीप गश्त के दौरान की गई। एसएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आमबारी कंपनी के जवान सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर जवानों ने कार्रवाई की। एसएसबी को देखते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल की ओर भाग निकला। हालांकि जवानों ने मौके से बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर ली। जब्त शराब नेपाल निर्मित है। बरामद 147 बोतलों में प्रत्येक बोतल 300 मिलीलीटर की है। कुल मिलाकर लगभग 44 लीटर नेपाली शराब जब्त की गई है। एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि बरामद शराब को जब्ती सूची तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए मद्य निषेध विभाग, अररिया के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में तस्कर की पहचान करने और उसके नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसबी 52वीं वाहिनी मुख्यालय, अररिया की ओर से जारी जानकारी में यह भी बताया गया कि सीमा क्षेत्र में तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। जवानों को सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

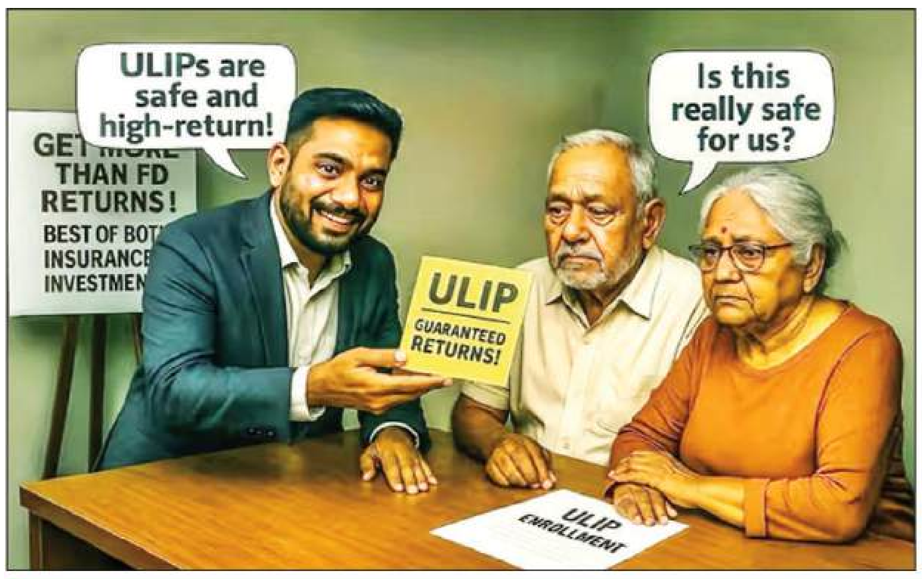

तस्वीर बदल चुकी है, दोबारा लौट रहे हैं यूलिप एफडी पर घटते ब्याज के बीच बन रहा विकल्प

नई दिल्ली

देश के प्रमुख बैंक अपने ग्राहकों को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) बेचने में सक्रिय हो गए हैं। इसकी मुख्य वजह है बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज का घटना। वहीं, यूलिप में बाजार से जुड़ा बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। बैंक इसे एक समग्र वित्तीय समाधान के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसमें बीमा कवर भी है और निवेश का अवसर भी।

हाल के वर्षों में यूलिप की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बीमा उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, निजी जीवन बीमा कंपनियों के कुल प्रीमियम संग्रह में यूलिप की हिस्सेदारी 50 फीसदी से अधिक हो चुकी है, जो बाजार में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।

पुराने से कितने अलग हैं नए यूलिप - एक दशक पहले भारी-भरकम शुल्क, कम रिटर्न और जटिल संरचना के कारण यूलिप की छवि खराब हो गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आईआरडीएआई के सख्त नियमों के बाद नए यूलिप में बड़े सुधार हुए हैं।

शून्य प्रीमियम एलोकेशन चार्ज: अब आपका पूरा प्रीमियम निवेश में लगता है।

शून्य पालिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज: प्रशासनिक खर्च की कोई कटौती नहीं।

लचीलापन: नए यूलिप में लचीलापन सबसे बड़ा नया फीचर है। निवेशक बाजार की स्थिति के अनुसार डेट और इक्विटी फंड के बीच असीमित स्विच कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

इक्विटी फंड की विविधता: निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड सहित कई प्रकार के इक्विटी फंड में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। नए यूलिप में मुख्य खर्च केवल फंड मैनेजमेंट चार्ज है, जो अधिकतम 1.35% प्रतिवर्ष तक सीमित है। यह म्यूचुअल फंड के खर्चों के करीब है। लंबी अवधि (10-15 वर्ष) में इक्विटी-आधारित यूलिप ने औसतन 10%-13% तक का रिटर्न दिया है, जो पारंपरिक बीमा योजनाओं के 4-5 फीसदी रिटर्न से कहीं बेहतर है।

क्या है यूलिप और किसके लिए बेहतर - यूलिप एक ऐसा उत्पाद है जो बीमा और निवेश को एक साथ जोड़ता है। प्रीमियम का एक हिस्सा मृत्यु लाभ के लिए और शेष हिस्सा चुने गए फंड में निवेश के लिए उपयोग होता है। यह प्लान उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो दीर्घकालिक (10 वर्ष या अधिक) निवेश करना चाहते हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

हुंडई एक्सटर पर ग्राहकों को आकर्षक छूट

नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी हुंडई इंडिया की हुंडई एक्सटर पर ग्राहकों को 43,000 रुपए तक के आकर्षक बेनिफिट्स दे रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.80 लाख रुपए से 9.45 लाख रुपए तक है, हालांकि जून से इसकी कीमत में 5,700 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की गई है। पेट्रोल से चलने वाले एमटी (एमटी) और एएमटी (एएमटी) गियरबाक्स वाले एस (एस), एस एक्जीक्यूटिव, एस स्मार्ट और एस प्लस ट्रिम्स पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट और 3,000 रुपए का सरकारी कर्मचारी या कार्पोरेट आफर मिल रहा है। टाप एसएक्स और एसएक्स (ओ) वैरिएंट्स पर 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा सीएनजी वैरिएंट्स पर है, जहां 43,000 रुपए तक के बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। एक्सटर फेसलिफ्ट के पेट्रोल और सीएनजी दोनों वैरिएंट्स पर 35,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है, जिसमें बेस एचएक्स2 को छोड़कर सभी ट्रिम्स शामिल हैं। फीचर्स की बात करें तो, हुंडई एक्सटर 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी जैसे सुरक्षा फीचर्स को सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर पेश करती है। इसमें कीलेस एंट्री, एलईडी टेल लैंप्स, 4.2 इंच एमआईडी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मैनुअल एसी जैसे फीचर्स बेस वैरिएंट से ही शुरू होते हैं। हायर वैरिएंट्स में टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम, 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्राइड आटो और एपल कारप्ले के साथ), रियर एसी वेंट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स मिलते हैं।

आनलाइन धोखाधड़ी: पैसे वापसी के लिए तुरंत करें ये काम

नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान ने जीवन को बेहद सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। फर्जी काल, फिशिंग लिंक और नकली ऐप्स के जरिए ठग लोगों के बैंक खातों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप आनलाइन फ्राड का शिकार हो जाएं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या आपका पैसा वापस मिल सकता है भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में ग्राहक को नुकसान की भरपाई मिल सकती है, बशर्ते वे समय पर कार्रवाई करें। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि धोखाधड़ी बैंक की गलती, तकनीकी खामी या किसी तीसरे पक्ष के कारण हुई है और ग्राहक की कोई भूमिका नहीं है, तो घटना की जानकारी के पाँच दिनों के भीतर शिकायत करने पर ग्राहक को पूर्ण सुरक्षा मिलती है और बैंक को पूरा नुकसान वहन करना होगा। हालांकि, शिकायत में 4-7 दिन की देरी होने पर ग्राहक की जिम्मेदारी सीमित हो सकती है, जो खाते के प्रकार पर निर्भर करेगी। वहीं, यदि ग्राहक स्वयं अपनी गोपनीय जानकारी साझा करता है, तो पैसे वापसी की संभावना बेहद कम हो जाती है।

ई-स्कूटर बारिश में भीग गया है, तो उसे तुरंत चार्जिंग पर न लगाएं

नई दिल्ली। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि बारिश में ई-स्कूटर चलाने से उसकी बैटरी खराब हो सकती है या उसमें शार्ट सर्किट हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो यह बात पूरी तरह सच नहीं है। आधुनिक ई-स्कूटर वाटरप्रूफ तकनीक से बनाए जाते हैं और ज्यादातर माडल आईपी67 या आईपी65 रेटिंग के साथ आते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी बैटरी और मोटर धूल और पानी की बौछारों से सुरक्षित हैं। इस तकनीक की वजह से तेज बारिश में भी स्कूटर चलाने से यह आमतौर पर खराब नहीं होता। लेकिन, कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। अगर सड़क पर आधे टायर से ज्यादा गहरा पानी भरा हो, तो ऐसे रास्तों से हमेशा बचना चाहिए। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से स्कूटर के कनेक्टर के अंदर नमी जा सकती है, जो मोटर कंट्रोलर के संवेदनशील हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है और आपको भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। बारिश के बाद चार्जिंग करते समय भी खास सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपका ई-स्कूटर बारिश में भीग गया है, तो उसे तुरंत चार्जिंग पर न लगाएं। नमी होने पर चार्ज करने से चार्जिंग साकेट में शार्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है।

अमेरिका ने 48 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे को दी मंजूरी, भारत की सैन्य क्षमता में होगा इजाफा

नई दिल्ली

अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकाप्टर और अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव और सहायता सेवाओं से संबंधित उपकरण बेचने की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित सौदे की कुल अनुमानित लागत 48.22 करोड़ अमेरिकी डालर है। अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कोआपरेशन एजेंसी (डीएससीए), जो विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) को मंजूरी देती है, उसने 17 जून को संघीय रजिस्टर में इस रक्षा बिक्री संबंधी अधिसूचना जारी की।

इससे पहले 18 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को अपाचे हेलीकाप्टरों और एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हावित्जर तोपों के लिए सहायता सेवाओं की संभावित बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया था। भारत ने अपनी तोपखाना क्षमता, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए अमेरिका से एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हावित्जर खरीदी थीं। वहीं भारतीय सेना एएच-64ई अपाचे अटैक हेलीकाप्टरों का भी संचालन करती है, जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकाप्टरों में गिना जाता है।

बोइंग, लाकहीड मार्टिन और बीएई सिस्टम्स होंगी प्रमुख कंपनियां

अपाचे हेलीकाप्टर सहायता कार्यक्रम के प्रमुख ठेकेदार बोइंग और लाकहीड मार्टिन होंगी। वहीं एम777 हावित्जर सहायता कार्यक्रम के लिए ब्रिटेन स्थित बीएई सिस्टम्स प्रमुख ठेकेदार होगी।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा बल

अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, हेलीकाप्टरों और हावित्जर तोपों के लिए प्रस्तावित सहायता पैकेज अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप है तथा इससे भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। विभाग ने कहा कि भारत हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। यह सौदा भारत की वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने, घरेलू रक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय खतरों को रोकने में मदद करेगा।

एम777 हावित्जर तोपों के लिए 23 करोड़ डालर का पैकेज

अधिसूचना के अनुसार, भारत ने एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हावित्जर के लिए दीर्घकालिक रखरखाव सहायता का अनुरोध किया है। इस पैकेज में सहायक उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत एवं वापसी सेवाएं, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, फील्ड सर्विस प्रतिनिधि, डिपो क्षमता विकास तथा लाजिस्टिक और कार्यक्रम सहायता से जुड़े तत्व शामिल होंगे। इस सहायता पैकेज की अनुमानित लागत 23 करोड़ डालर बताई गई है।

अपाचे हेलीकाप्टरों के लिए 19.82 करोड़ डालर का समर्थन पैकेज

एक अलग अधिसूचना में अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि भारत ने एएच-64ई अपाचे हेलीकाप्टरों के लिए रखरखाव सहायता सेवाएं, अमेरिकी सरकार और निजी ठेकेदारों की इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं लाजिस्टिक सहायता, तकनीकी दस्तावेज, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित कार्यक्रम सहायता की मांग की है।

अपाचे हेलीकाप्टरों के लिए प्रस्तावित सहायता पैकेज की अनुमानित लागत 19.82 करोड़ डालर है।

सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 एफएफवी पर किए फ्यूल ई85 टेस्ट में मिले चौकाने वाले नतीजे

नई दिल्ली

सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 एफएफवी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर किए गए एक हालिया माइलेज टेस्ट ने चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, जिससे यह पता चलता है कि कम कीमत के बावजूद ई85 फ्यूल पर गाड़ी चलाना ई20 की तुलना में महंगा पड़ सकता है। यह माइलेज टेस्ट शहर के एक ही 80 किलोमीटर के रास्ते पर ई85 और ई20 दोनों फ्यूल के लिए किया गया, ताकि ट्रैफिक की स्थिति लगभग एक जैसी रहे। टेस्ट के दौरान ई85 के साथ फ्यूल एफिशिएंसी 28.81 किलोमीटर प्रति लीटर सामने आई, जबकि ई20 के साथ यह आंकड़ा 38.10 केएमपीएल निकला। इस प्रकार, दोनों के बीच फ्यूल एफिशिएंसी में लगभग 9.29 केएमपीएल या 24.40 प्रतिशत का महत्वपूर्ण अंतर देखा गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रति किलोमीटर की लागत की गणना की जा सकती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो, ई20 पर चलने की लागत लगभग 2.68 रुपए प्रति किलोमीटर बैठती है। वहीं, ई85 फ्यूल के साथ, लागत 2.85 रुपए प्रति किलोमीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि ई85 को चलाने की वास्तविक लागत ई20 से अधिक है, भले ही ई85 को कम कीमत पर पेश किया जा रहा हो। यूजर्स को ई20 की तुलना में ई85 के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर लगभग 17 पैसे अधिक भुगतान करना होगा। एक और बात जो ई85 के पक्ष में नहीं जाती, वह यह है कि ई85 सपोर्ट वाले टू-व्हीलर्स की कीमत भी स्टैंडर्ड ई20 वर्जन की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक होती है।

इसका मतलब है कि ग्राहकों को न केवल बाइक खरीदते समय प्रीमियम का भुगतान करना होगा, बल्कि चलाने की अधिक लागत भी वहन करनी पड़ेगी। ये कारण वास्तव में ग्राहकों को ई85 वाहनों को खरीदने से थोड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि इथेनाल फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बावजूद, वास्तविक बचत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मालूम हो कि आटोमोबाइल कंपनियां अपने टू-व्हीलर्स में इथेनाल सपोर्ट इंजन लगाना शुरू कर चुकी हैं, जो ई20 से ई85 फ्यूल को सपोर्ट करते हैं। देश में ई85 फ्यूल की उपलब्धता भी शुरू हो गई है, जिसकी कीमत 82.12 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जबकि ई20 फ्यूल 102.12 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है।

लंबी यात्रा में सुरक्षा और माइलेज के लिए जरूरी है नाइट्रोजन हवा

नई दिल्ली। लंबी यात्रा के दौरान गाड़ियों के टायरों में अक्सर लोग साधारण हवा भरवाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अब टायरों में नाइट्रोजन हवा भरवाने की सलाह देते हैं। हाईवे पर सफर करते समय गाड़ियों के टायरों का सही चुनाव और उनमें सही हवा का भराव बेहद महत्वपूर्ण होता है। सामान्य पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली साधारण हवा में लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21प्रतिशत आक्सीजन और 1प्रतिशत अन्य गैसें व नमी होती है, जबकि टायरों में भरी जाने वाली नाइट्रोजन लगभग 93 से 95प्रतिशत तक शुद्ध होती है, जिसमें आक्सीजन और नमी की मात्रा न के बराबर रहती है। नाइट्रोजन हवा के कई फायदे हैं। जब गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार में चलती है, तो सड़क और टायर के बीच घर्षण से टायर गर्म हो जाते हैं। साधारण हवा में मौजूद आक्सीजन गर्मी पाकर तेजी से फैलता है, जिससे टायर का दबाव बढ़ जाता है और टायर फटने का खतरा रहता है। वहीं, नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है जो जल्दी गर्म नहीं होती। यह टायर के तापमान को नियंत्रित रखती है और दुर्घटना के जोखिम को कम करती है।

सोना-चांदी बाजार में हल्की गिरावट देशभर में कीमतों में नरमी का रुख

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सांकेतिक कमजोरी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,48,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोना 1,33,890 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,35,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,46,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,46,120 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,48,360 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,35,990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,33,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,120 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,46,220 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट

सोना 1,34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,120 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,33,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,46,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद हुए थे। हालांकि, डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एशियाई बाजार में भी मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रोग्रेस होने की खबर की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान खरीदारी का माहौल बना रहा। एस एंड पी 500 इंडेक्स 80.48 अंक यानी 1.08 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,500.58 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 496.28 अंक यानी 1.91 प्रतिशत कि छलांग लगा कर 26,517.93 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 110 अंक

यानी 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 51,454.70 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.41 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,356.88 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,432.80 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके विपरीत डीएएक्स इंडेक्स 0.12 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 25,057.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में भी मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से छह के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स बड़ी गिरावट का शिकार हो गया है। फिलहाल यह सूचकांक 109.30 अंक यानी 1.77 प्रतिशत टूट कर 6,067.84 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 208.81 अंक यानी 0.87 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,716 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.13 प्रतिशत फिसल कर 5,185.98 अंक के स्तर पर आ गया है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.35 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,132 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,577.63 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। ताइवान वेटेड इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,357.34 अंक यानी 2.92 प्रतिशत उछल कर 47,822.54 अंक के स्तर पर आ गया है।

इसी तरह निक्केई इंडेक्स भी जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। फिलहाल यह सूचकांक 1,532.94 अंक यानी 2.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,783 अंक के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा कोस्पी इंडेक्स 88.98 अंक यानी 0.98 प्रतिशत की मजबूती के साथ 9,141.40 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,098.01 अंक के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं।

फीफा विश्व कप 2026 : मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3–1 से हराकर दर्ज की विश्व कप इतिहास की पहली जीत

वैंकूवर

स्टार फुटबालर मोहम्मद सालाह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मिस्र ने सोमवार को फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रच दिया। ग्रुप-जी के मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप इतिहास की अपनी पहली जीत दर्ज की।

मिस्र के लिए मोहम्मद सालाह और मुस्तफा ज़िको ने एक-एक गोल करने के साथ एक-एक गोल में सहयोग भी किया, जबकि तीसरा गोल ट्रेज़ेगेट ने किया। पहले हाफ में पिछड़ने के बाद मिस्र ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और ग्रुप-जी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड ने मैच की शुरुआत शानदार तरीके से की और 15वें मिनट में फिन सुरमैन ने कार्नर से मिले मौके को हेडर में बदलकर टीम को बढ़त दिला दी। पहले हाफ तक न्यूजीलैंड 1-0 से आगे रहा। दूसरे हाफ में मिस्र ने आक्रामक खेल दिखाया। 58वें मिनट में मोहम्मद हानी के बेहतरीन क्रास पर मुस्तफा ज़िको ने हेडर लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया।

इसके बाद 67वें मिनट में सालाह ने टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागते हुए मिस्र को बढ़त दिला दी। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 68वां गोल भी रहा। गोल के बाद सालाह ने दर्शकों की ओर मुट्ठी लहराकर जश्न मनाया और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया।

82वें मिनट में ट्रेज़ेगेट ने कार्नर पर शानदार हेडर लगाकर मिस्र की जीत पक्की कर दी। यह विश्व कप में उनका पहला गोल रहा। मिस्र के गोलकीपर मुस्तफा शोबीर ने चार महत्वपूर्ण बचाव किए, जबकि न्यूजीलैंड के गोलकीपर मैक्स क्रोकाम्बे ने भी चार सेव किए।

इस जीत के बाद मिस्र ग्रुप में मजबूत स्थिति में पहुंच गया है और शुक्रवार को ईरान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मुकाबला खेलेगा। वहीं न्यूजीलैंड, जो अब भी विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश में है, उसी दिन बेल्जियम से भिड़ेगा।

मैच के बाद सालाह ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस जीत को मिस्र के फुटबाल इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। उन्होंने मिस्री समर्थकों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे टीम अपने ही देश में खेल रही हो।

न्यूज ब्रीफ

फीफा विश्व कप 2026 : इराक के खिलाफ फ्रांस के लिए 100वां मैच खेलेंगे एम्बाप्पे

फिलाडेल्फिया। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे सोमवार को इराक के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-आई मुकाबले में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 100वां मैच खेलने उतरेंगे।

मुकाबले से पहले फिलाडेल्फिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए बेहद खास है। एम्बाप्पे ने कहा कि अपने देश के लिए खेलना हमेशा गर्व की बात होती है और विश्व कप जैसे मंच पर 100 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पूरे करना इसे और भी यादगार बना देता है। उन्होंने कहा कि सौ का आंकड़ा ऐतिहासिक होता है और विश्व कप में इस उपलब्धि तक पहुंचना उनके लिए विशेष क्षण होगा। 27 वर्षीय एम्बाप्पे फ्रांस के लिए 100 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि वह अभी भी पूर्व कप्तान और गोलरक्षक ह्यूगो लोरिस के 145 मुकाबलों के रिकार्ड से पीछे हैं। हाल ही में सेनेगल के खिलाफ दो गोल कर एम्बाप्पे फ्रांस के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके नाम अब 58 अंतरराष्ट्रीय गोल दर्ज हैं और उन्होंने ओलिवियर जिरू का रिकार्ड पीछे छोड़ दिया है। एम्बाप्पे ने कहा कि व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा उनके लिए टीम की सफलता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इराक के खिलाफ जीत टीम को अगले चरण के करीब पहुंचाएगी और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विश्व कप को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपने देश के लिए इतिहास में याद किए जाना चाहते हैं और विश्व कप जैसा मंच किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी क्षमता दिखाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। विश्व कप में सर्वाधिक गोल के रिकार्ड की चर्चा पर एम्बाप्पे ने कहा कि वह लगातार गोल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य फ्रांस को अधिक से अधिक आगे ले जाना है।

फीफा विश्व कप 2026 : 10 खिलाड़ियों के साथ ईरान ने बेल्जियम को गोलरहित ड्रा पर रोका

लास एंजिलिस। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-जी मुकाबले में रविवार को बेल्जियम को ईरान के खिलाफ निराशा हाथ लगी। पूरे मैच में दबदबा बनाने के बावजूद बेल्जियम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए ईरान की मजबूत रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सका और मुकाबला 0-0 से ड्रा पर समाप्त हुआ। दक्षिणी कैलिफोर्निया में खेले गए इस मुकाबले में दर्शकों का बड़ा समर्थन बेल्जियम को मिला, लेकिन ईरान ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाते हुए अंक बांटने में सफलता हासिल की। ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंद टीम के सबसे बड़े नायक साबित हुए। उन्होंने पूरे मैच में सात महत्वपूर्ण बचाव किए और बेल्जियम के लगातार हमलों को विफल कर दिया। बेल्जियम ने गेंद पर अधिक नियंत्रण बनाए रखा और कई मौके बनाए, लेकिन दूसरे हाफ में टीम को बड़ा झटका लगा जब डिफेंडर नाथन न्गोय को लाल कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। उन्होंने गोल की ओर बढ़ रहे ईरानी स्ट्राइकर मेहदी तारेमी को रोकने के प्रयास में फाउल किया था। एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद बेल्जियम ने हमले जारी रखे, लेकिन ईरान की अनुशासित रक्षा के सामने उसे सफलता नहीं मिली।

यशस्वी ने पिता को फादर्स डे पर लक्जरी कार उपहार में देकर जीता दिल

मुम्बई। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने फादर्स डे के अवसर पर अपने पिता को एक महंगी लग्जरी कार उपहार में दी है।

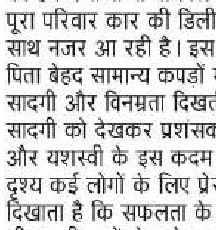

इस कार की कीमत करीब बेहद 1.32 करोड़ रुपये बतायी गयी है। यशस्वी के अपने पिता को उपहार देने पर प्रशंसकों ने उनकी जमकर प्रशंसा की है। यश्स्वी ने जिस प्रकार से पिता को कार भेंट की है। उससे उन्होंने उनके प्रति गहरे सम्मान और प्रेम को दिखाया है। इसका कारण ये है कि पिता ने यशस्वी के क्रिकेट सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया था। पिता को कार उपहार में देने की दिल जीत लेने वाली तस्वीरें यशस्वी के भाई तेजस्वी ने सोशल मीडिया में साझा की हैं। ये तेजी से वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में पूरा परिवार कार की डिलीवरी लेने के लिए एक साथ नजर आ रही है। इस दौरान यशस्वी के माता-पिता बेहद सामान्य कपड़ों में दिखे, इससे उनकी सादगी और विनम्रता दिखती है। उनके पिता की इस सादगी को देखकर प्रशंसक भी बेहद भावुक हो गए और यशस्वी के इस कदम की सराहना की। यह दृश्य कई लोगों के लिए प्रेरणादायक था, क्योंकि यह दिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरुरी है। यशस्वी ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज के अंतिम मुकाबले में शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलायी थी।

चंचल राठौर की कप्तानी पारी से उज्जैन फाल्कंस की शानदार जीत

प्लेयर आफ द मैच आर्यन पांडे की हैट्रिक और आलराउंड खेल से पस्त हुई बुल्स ; दर्शन राठौर ने छक्के से किया मैच फिनिश

इंदौर

होलकर स्टेडियम में खेले गए मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2026 के 39वें मुकाबले में उज्जैन फाल्कंस ने रोमांचक संघर्ष के बाद बुंदेलखंड बुल्स को चार विकेट से पराजित कर प्लेआफ की उम्मीदों को मजबूती दी। 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उज्जैन फाल्कंस ने कप्तान चंचल राठौर (63) और प्लेयर आफ द मैच आर्यन पांडे (24 रन व 4 विकेट) के दमदार प्रदर्शन की बदौलत 19.1 ओवर में 166/6 रन बनाकर चार विकेट से जीत हासिल की।

टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बुंदेलखंड बुल्स ने कप्तान अभिषेक पाठक की 14 गेंदों में 36 रन की विस्फोटक पारी और शिवांग कुमार (30) तथा विक्रांत भदौरिया (22) के योगदान से 19.5 ओवर में 160 रन बनाए। बुल्स ने पावरप्ले में 72 रन जोड़कर आक्रामक शुरुआत की, लेकिन बाद के ओवरों में नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। उज्जैन की ओर से आर्यन पांडे ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 16 रन देकर चार विकेट झटके। उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में लगातार तीन गेंदों पर गौतम जोशी, ओमकार नाथ सिंह और हर्षित परसाई को आउट कर शानदार हैट्रिक भी पूरी की। मसूम रज़ा कैफ ने 19 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।

161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उज्जैन फाल्कंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 13 रन के स्कोर पर ऋषि मिगलानी और यश दुबे के विकेट गंवा दिए। इसके बाद माधव तिवारी ने 10 गेंदों में 20 रन की तेज पारी खेलकर रनगति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर्षित परसाई ने उन्हें पवेलियन भेजकर फाल्कंस को तीसरा झटका दिया। पावरप्ले में टीम का स्कोर 47/3 रहा और मुकाबला पूरी तरह बुंदेलखंड बुल्स के पक्ष में दिखाई देने लगा।

संकट की इस घड़ी में कप्तान एवं विकेटकीपर चंचल राठौर ने शानदार जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 50 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल रहे। चंचल ने ओजस्वा यादव (38) के साथ चौथे विकेट के लिए 85 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मुकाबले में वापस ला दिया। यह साझेदारी मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई।

जब जीत के लिए तेज रन चाहिए थे, तब आर्यन पांडे ने भी बल्ले से कमाल दिखाया। उन्होंने 16 गेंदों में 24 रन की उपयोगी पारी खेलकर दबाव कम किया और फाल्कंस को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। अंतिम दो ओवरों में मुकाबला फिर रोमांचक हो गया, जब रुद्रांश सिंह ने 19वें ओवर में पहले चंचल राठौर और फिर आर्यन पांडे को आउट कर बुल्स की उम्मीदों को जगा दिया। हालांकि अंकुर सिंह चौहान और दर्शन राठौर ने घबराहट नहीं दिखाई। अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर दर्शन राठौर ने भुमेश मुजालदा को शानदार छक्का जड़कर मैच का अंत किया और उज्जैन फाल्कंस को यादगार जीत दिला दी। दर्शन 4 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि अंकुर सिंह चौहान 5 रन बनाकर अविजित रहे।

एक ही गलती दोहराने के कारण शतक नहीं लगा पा रहे वैभव

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पदार्पण के बाद से ही अपने शानदार प्रदर्शन से छाये हुए हैं पर लगातार एक गलती दोहराने के कारण अपना शतक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब तक वह चार बर शतक के करीब आकर भी उसे बनाने में विफल रहे हैं। जिससे प्रशंसक भी निराश हैं। भारत ए टीम की ओर से श्रीलंका दौरे में भी वैभव ने यही गलती की है। इससे 94 रनों पर पहुंचने के बाद भी वह शतक नहीं लगा पाये। इसका कारण उनमें धैर्य की कमी को माना जा रहा है। वैभव अगले माह होने वाले इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए सीनियर टीम में शामिल किये गये हैं। ऐसे में प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि वह एक ही गलती अब नहीं करेंगे। वैभव ने हाल ही में श्रीलंका दौरे पर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में केवल 29 गेंदों में ही 94 रनों की आतिशी पारी खेली थी जिससे सभी हैरान हो गये थे। इस आक्रामक पारी के बाद भी वैभव शतक के बेहद करीब पहुंचकर भी उसे पूरा नहीं कर पाये। इससे एक बार फिर दिखा कि वह शतक के करीब जाकर गलती कर जाते हैं। श्रीलंका ए के खिलाफ हुए उस फाइनल मुकाबले में वैभव ने पहली गेंद से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 11 गेंदों में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। 64 रन तक पहुंचने तक वैभव ने एक भी सिंगल नहीं लिया, जो यह संकेत दे रहा था कि वह एक बड़े शतक की ओर बढ़ रहे हैं पर एक बार फिर इस बल्लेबाज ने वही पुरानी गलती दोहराई जिससे वह शतक से केवल 6 रन दूर रह गए।

आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने पर बोले प्रीतम- तकनीक पर रखा पूरा ध्यान

सुहल (जर्मनी)

भारत के 16 वर्षीय निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार पहचान बनाते हुए आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। अपने केवल दूसरे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए प्रीतम ने आठ खिलाड़ियों के फाइनल में बेहद संयमित और शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 251.3 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तटस्थ खिलाड़ी तिमोफेई अलेइनिकोव ने रजत और नार्वे के जेन्स ओएस्टली ने कांस्य पदक जीता।

विश्व खिताब जीतने के बाद प्रीतम ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान उनका पूरा ध्यान केवल अपनी तकनीक और हर शाट को बेहतर तरीके से खेलने पर था। प्रीतम ने एक आधिकारिक बयान में कहा, इस जीत से मैं बेहद खुश हूं। पूरी प्रतियोगिता के दौरान मेरा ध्यान केवल अपनी तकनीक पर रहा और हर शाट में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। पुणे के रहने वाले युवा निशानेबाज ने अपनी सफलता का श्रेय गगन नारंग गन फार ग्लोरी शूटिंग अकादमी को भी दिया। उन्होंने कहा, अकादमी के प्रशिक्षकों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी मार्गदर्शन दिया। हमारी तैयारी हमेशा तकनीक सुधारने पर केंद्रित रही और मुझे लगता है कि यही इस सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। हाल ही में दसवीं की परीक्षा पूरी करने वाले प्रीतम ने कहा कि यह उपलब्धि उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, विश्व चैम्पियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। मैं 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में लगातार बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूं और भारत के लिए आने वाले वर्षों में कई और पदक जीतना चाहता हूं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैम्पियनशिप का यह पांचवां संस्करण जर्मनी के सुहल में आयोजित हो रहा है, जिसमें 70 राष्ट्रीय महासंघों के 800 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में 84 सदस्यीय दल उतारा है। इससे पहले 2024 में पेरू के लीमा में आयोजित प्रतियोगिता में भारत 24 पदकों (13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य) के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था।

धीमी ओवर गति पर इंग्लैंड को बड़ा झटका, 12 डब्ल्यूटीसी अंक कटे

लंदन। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहली बार पहुंचने की इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण इंग्लैंड के 12 डब्ल्यूटीसी अंक काट लिए गए हैं। ओवल टेस्ट में न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला बराबर कर दी। मैच के बाद यह पाया गया कि इंग्लैंड निर्धारित समय के मुकाबले 12 ओवर पीछे रहा। इसके चलते टीम पर अंक कटौती के साथ-साथ खिलाड़ियों की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने बयान में कहा कि इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान जो रूट ने गलती स्वीकार कर ली और प्रस्तावित दंड को मान लिया, जिसके बाद औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस दंड के बाद विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका में इंग्लैंड सातवें स्थान पर बना हुआ है, लेकिन उसका अंक प्रतिशत 34.72 से घटकर 26.38 हो गया है। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका की शीर्ष दो टीमें अगले वर्ष लार्ड्स में होने वाले फाइनल में आमने-सामने होंगी। फिलहाल शीर्ष दो स्थानों पर आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका काबिज हैं।

चार साल बाद सिंगल्स कोर्ट पर वापसी करेंगी सेरेना, विंबलडन 2026 के लिए मिला वाइल्डकार्ड

लंदन

दिग्गज अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स एक बार फिर ग्रैंड स्लैम मंच पर वापसी करने जा रही हैं। 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना को विंबलडन 2026 के सिंगल्स वर्ग के लिए अंतिम वाइल्डकार्ड दिया गया है। इसके साथ ही वह लगभग चार साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में सिंगल्स मुकाबला खेलती नजर आएंगी।

44 वर्षीय सेरेना पहले ही अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स के साथ डबल्स वर्ग में वाइल्डकार्ड हासिल कर चुकी थीं, लेकिन अब सिंगल्स में भी उनकी एंट्री ने खेल प्रेमियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।

सात बार की विंबलडन चैंपियन सेरेना ने आखिरी बार वर्ष 2022 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। उस दौरान उन्हें पहले दौर में फ्रांस की खिलाड़ी हार्मनी तान से हार का सामना करना पड़ा था। उसी वर्ष अमेरिकी ओपन में उनका सफर तीसरे दौर में समाप्त हुआ था।

उस समय सेरेना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की थी और कहा था कि वह खेल से आगे एक नए चरण में आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि पिछले वर्ष उनके दोबारा एंटी-डोपिंग परीक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी वापसी की चर्चाएं तेज हो गई थीं।

हाल ही में उन्होंने टेनिस कोर्ट पर वापसी करते हुए कनाडा की युवा खिलाड़ी विक्टोरिया म्बोको के साथ डबल्स मुकाबले खेले। इसके बाद उन्होंने चेक गणराज्य की खिलाड़ी करोलिना मुचोवा के साथ भी डबल्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब सभी की नजरें विंबलडन पर होंगी, जहां सेरेना एक बार फिर सिंगल्स कोर्ट पर उतरकर अपने शानदार करियर में नया अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगी। इस वर्ष विंबलडन प्रतियोगिता 29 जून से 12 जुलाई तक आयोजित की जाएगी।

महिला टी20 विश्व कप में भारत की पहली हार, दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से हराया

मैनचेस्टर

आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को छह विकेट से पराजित कर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी आलराउंडर मारिजान कैप ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई।

टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की। शेफाली वर्मा ने तेज बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवरों में रन गति को बनाए रखा, जबकि स्मृति मंधाना ने भी उपयोगी योगदान दिया। पावरप्ले में भारत ने तेज शुरुआत का फायदा उठाया, लेकिन इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी।

मध्यक्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा

और अन्य बल्लेबाजों ने उपयोगी पारियां खेलीं, जिससे भारत निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 158 रन तक पहुंच सका। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत धीमी रही और शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया। भारतीय स्पिनरों ने शुरुआती सफलताएं दिलाकर टीम को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद मारिजान कैप और ताजमिन ब्रिट्स ने संयमित और आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार मिश्रण पेश किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापस ला दिया। कैप ने अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी करते हुए भारत की जीत की उम्मीदों को समाप्त कर दिया। भारतीय टीम को बीच के ओवरों में कैप को आउट करने के अवसर भी मिले, लेकिन कुछ कैच छूटने का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। अंतिम दो ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अपेक्षाकृत कम रन चाहिए थे और कैप ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। मारिजान कैप ने आलराउंड प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और बल्लेबाजी में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया। इस हार के बावजूद भारतीय टीम अंक तालिका में मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अब टीम की नजर अगले मुकाबले पर होगी, जहां जीत उसे सेमीफाइनल की दौड़ में और मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है।

सत्यमेव जयते

75TH FOUNDATION DAY

Platinum Jubilee

KARBI ANGLONG AUTONOMOUS COUNCIL · DIPHU · Justice-Equality-Service · ESTD. 1952

KARBI ANGLONG AUTONOMOUS COUNCIL, DIPHU

- 75 Years of Progress: Celebrating a historic milestone of self-governance, cultural pride, and development.
- Historic Formation: Established on June 23, 1952, under the Sixth Schedule of the Indian Constitution.
- Protecting Our Heritage: Formed to safeguard the land rights and rich traditions of our indigenous communities.
- Evolution to Autonomy: Grown from its early roots into the fully empowered Karbi Anglong Autonomous Council in 1995.
- A United Vision: Honoring the resilience of our people as we build a prosperous future for the indigenous people of Karbi Anglong and West Karbi Anglong

DR. TULIRAM RONGHANG
HON'BLE CEM, KAAC

RANGSINA SARPO AHONGJAI
TARALANGSO, DIPHU
23rd June, 2026

IPRD/KACC/2026-27/71

FROM THE HILLS, TOWARDS GREATER HEIGHTS

Honouring the Past + Celebrating the Present + Inspiring the Future

Published by IPRD, KAAC, Diphu

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय) e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, (सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)